सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 74, नई दिल्ली । रविवार, 26 मई 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

कुछ कर सकने में सफलता आती है और कुछ ना कर सकने में असफलता आती है।

03 दिल्ली में 7 सीटों पर काटती धूप के बीच बंपर वोटिंग
06 संवैधानिक व्यवस्था से ऊपर नहीं ममता सरकार
08 महेश आरोग्य किट जीवन रक्षक के लिए कारगर -महंत लक्ष्मण दास त्यागी

राष्ट्र के लिए वोट: मतदाता असली परिवर्तनकर्ता हैं, समाज के असली नायक हैं

मतदान का कार्य लोकतांत्रिक समाजों की आधारशिला है, जो लोगों की इच्छा को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि उनके देश के शासन में उनकी आवाज़ सुनी जाए। यह रिपोर्ट मतदाताओं, विशेषकर युवाओं के योगदान पर प्रकाश डालती है, जिन्होंने हाल के चुनावों में भाग लिया था, जिसमें फ़रीदाबाद में पहली बार मतदाताओं के अनुभवों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

सभी मतदाताओं का सम्मान

हम उन सभी व्यक्तियों के प्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त करते हैं जिन्होंने मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया। विविध पृष्ठभूमि के मतदाताओं द्वारा दिखाई गई प्रतिबद्धता हमारे लोकतंत्र की ताकत को मजबूत करती है। डाला गया प्रत्येक वोट हमारे राष्ट्र के बेहतर भविष्य को आकार देने की दिशा में एक कदम का प्रतिनिधित्व करता है।

फ़रीदाबाद में युवाओं की भागीदारी

अपने औद्योगिक महत्व और जीवंत समुदाय के लिए मशहूर शहर फ़रीदाबाद में पहली बार मतदान करने वालों का उत्साह विशेष रूप से उल्लेखनीय था। मतदाताओं के एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाले युवाओं ने चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सराहनीय उत्सुकता दिखाई।

पहली बार मतदाताओं के लिए एक अविश्वसनीय अनुभव

पहली बार वोट डालने का अनुभव किसी युवा व्यक्ति के जीवन में एक मील का पत्थर होता है। फ़रीदाबाद में, कई युवाओं ने उत्साह, गर्व और जिम्मेदारी की भावना का मिश्रण दर्शाते हुए अपने अनुभव साझा किए। यहाँ कुछ झलकियाँ हैं:

रुद्र : पहली बार मतदान करने से मुझे राष्ट्र का अभिन्न अंग होने का एहसास हुआ। मुझे लगा कि मेरा वोट एक अंतर ला सकता है, और यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में योगदान करने के लिए सशक्त है।"

रोहित शर्मा : "मैं चिंतित लेकिन उत्साहित था। पूरी प्रक्रिया सुचारू थी, और चुनाव अधिकारी बहुत सहयोगी थे। यह एक ऐसा दिन है जिसे मैं हमेशा याद रखूंगा।"

तान्या : "मैं हाल ही में विदेश से पढ़ाई के बाद भारत आई हूं और वोट डालना एक अद्भुत अनुभव है - मेरे समुदाय के इतने सारे लोगों को वोट देने के लिए बाहर आते देखना प्रेरणादायक था।"

समुदाय से समर्थन

मतदान प्रतिशत को प्रोत्साहित करने में समुदाय का समर्थन महत्वपूर्ण था। स्थानीय संगठनों और स्वयंसेवकों ने नागरिकों को मतदान के महत्व के बारे में शिक्षित करने और यह सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभाई कि पहली बार मतदाता अच्छी तरह से तैयार हों।

सामुदायिक पहल

मतदाता भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की गईं:

जागरूकता अभियान: विभिन्न गैर सरकारी संगठनों और सामुदायिक समूहों ने युवाओं को शामिल करने के लिए स्कूलों और कॉलेजों को लक्षित करते हुए, मतदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान आयोजित किए।

मतदाता पंजीकरण अभियान: मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के प्रयास किए गए, स्वयंसेवकों ने युवाओं को मतदान के लिए पंजीकरण कराने में सहायता की।

कार्यशालाएँ और सेमिनार: मतदान प्रक्रिया, सूचित मतदान के महत्व और प्रत्येक वोट कैसे मायने रखता है, यह समझाने के लिए शैक्षिक कार्यशालाएँ आयोजित की गईं।

रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा विशेष अभियान, मतदाताओं विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों का समर्थन करने के लिए स्वयंसेवकों को प्रदान किया गया, कुछ सोसाइटी ने लोगों के लिए ई रिक्शा प्रदान किया, सप्रिंगफील्ड फ़रीदाबाद से स्थानीय निवासियों और सदस्यों द्वारा वोट डालने के लिए घर-घर अभियान पर विशेष जोर दिया गया। मतदाता असली परिवर्तनकर्ता हैं, समाज के असली नायक हैं इसलिए गौरवान्वित नागरिक हैं, जय हिंद।

- अंकुर शरण

दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन द्वारा पूरी तरह से किया गया लोकसभा 2024 के चुनाव का बाहिष्कार

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन द्वारा लोकसभा 2024 के चुनाव का बाहिष्कार पूरी तरह टैक्सी बस मालिकों/चालकों द्वारा किया गया।

ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट का कहना हैं की हम सब को बड़ा दुख हैं की हमने वोट नहीं डाले, हमें इस बात का भी दुख और भी ज्यादा हैं की लोकतंत्र को मजबूत करने वाला इलेक्शन कमिसन और सारी मुख्य पार्टी के अध्यक्ष से लेकर दुसरे पदाधिकारीयों ने इस बात का संज्ञान नहीं लिया की दिल्ली के टैक्सी बस वाले और उनके चालक 10 साल से अपनी जायज मांगो के लिए लड़ रहें हैं और जबकि हमने प्रेस क्लब ऑफ़ इंडिया दिल्ली में 24 अप्रैल 2024 को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव बहिष्कार की घोषणा कर दी थी और इसके बावजूद अपनी मांगो को पूरा करवाने के लिए और लोकतान्त्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए और हम वोट डालने की प्रक्रिया को पूरा करें इस उदेश्य से भी हमने सभी मुख्य राजनितिक पार्टी के मंत्रियो और उनके अध्यक्ष और पदाधिकारी से मिलने का समय तक माँगा जिसमे की वो हमें अस्वासन दें सके की चुनाव के बाद हमारी मांगो पर गौर करेंगे लेकिन किसी भी राजनितिक पार्टी के लोगों ने हमें समय नहीं दिया और ना ही कोई अस्वासन हमें उनकी तरफ से मिला।

क्योंकी लगभग 10 साल सालो से हमारी जायज मांगो को सरकारों द्वारा अनुसूना किया जा रहा हैं

1:- पैनिक बटन के नाम पर करोंड़ो रूपए का भ्रष्टाचार हो रहा हैं. महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर एक भद्दा मज़ाक बनाया गया हैं.

2:- स्पीड लिमिट डिवाइस (स्पीड गवर्नर) के कारण

महिलाओ की सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा हैं, महिलाओ की इज्जत और उनकी जानमाल को खतरा हैं.

3:- MCD टोल टैक्स के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा हैं

4:- प्रदूषण के नाम पर गाड़ियों को स्क्रीप(कूड़ा)बनाया जा रहा हैं.

5:- प्रदूषण के नाम पर ग्रेप सिस्टम लगाकर 20 हजार तक के जुर्माने करें जाते हैं.

6:-RFID MCD टोल टैक्स से नाजायज पैसे लगातार काटे जा रहें हैं.

7:-उत्तर प्रदेश के डिसट्रिक्ट मजिस्ट्रेट /चुनाव अधिकारी द्वारा टूरिस्ट बसों को जबरजस्ती छीन कर उन्हें इलेक्शन ड्यूटी मे लगा कर उन बसों के पैसे भी नहीं दिए गए .

8:-आल इंडिया टूरिस्ट परमिट की सालना फीस भरने के बावजूद जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश दोबारा से रोड टैक्स वसूल रहें हैं.

9.बड़े हुए ट्रैफिक चालान की राशि वापिस कम की जाए क्योंकी इस की वजह से भ्रष्टाचार बड़ा है.

25 मई का दिन लोकतंत्र पर काला अध्याय की तरह रहेगा क्योंकी दिल्ली जैसे शहर में जो की भारत की राजधानी हैं वहीँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है ज़्यादती हो रहीं लोगों पर और कोई सुनने वाला नहीं है, तो आप सब लोग अंदाजा लगा सकते है की देश के दुसरे शहरो में क्या हाल होगा ?

ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट का कहना है की अँचार सहिंता हटते ही हम

इन सब मुद्दों फिर धरने प्रदर्शन करके अपनी मांगे मनवाएंगे.

और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता की केंद्र में कौनसी सरकार आएगी क्योंकी चाहे केंद्र में सरकार हो या दिल्ली में ये सब टैक्सी बस वालो और उनके चालकों का ही शोषण करते है और करेंगे. क्योंकी इन्हे पता है की अगर वोटिंग प्रतिशत कितना भी हो ये सांसद बन ही जाएंगे.

संजय सम्राट का कहना है जहाँ भी वोट प्रतिशत 70% से कम हो वहाँ के चुनाव को केंसिल करा देना चाहिए और उस शहर या सीट पर 5 साल बाद ही चुनाव होना चाहिए क्योंकी जब ये वोटर की कीमत जानेंगे तभी लोगों के काम होंगे और उनकी सुनवाई होंगी. तभी भारत में लोकतंत्र मजबूत होगा।

पर्यावरण पाठशाला : पेड़ बचाने की अपील: पूजा में भोजन और चींटियों को खिलाने से बचें, पेड़ बचाएंगे तो हम बचेंगे

प्रिय पाठक,

हम सभी जानते हैं कि पेड़ों का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। विशेषकर पीपल और बरगद जैसे पेड़, जो न केवल पर्यावरण को शुद्ध करते हैं, बल्कि हमें शीतल छाया और सांस्कृतिक महत्व भी प्रदान करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूजा के दौरान पेड़ों के पास भोजन रखने या चींटियों को खिलाने से उनके जीवन पर बुरा असर पड़ सकता है? आइए, इस पर गहराई से विचार करें और इन पवित्र पेड़ों को बचाने के लिए एक अपील करें।

चींटियों को खिलाने से होने वाले नुकसान

चींटियों को खिलाने से पेड़ों के आसपास उनकी संख्या बढ़ जाती है। यह समस्याएँ पैदा कर सकता है:

पेड़ की जड़ों को नुकसान: चींटियाँ पेड़ की जड़ों में सुरंग बना सकती हैं, जिससे जड़ें कमजोर हो जाती हैं और पेड़ को पोषक तत्वों की आपूर्ति में कमी हो जाती है।

कीटों का आकर्षण: चींटियाँ अन्य हानिकारक कीटों को आकर्षित कर सकती हैं जो पेड़ को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

भोजन रखने से होने वाले नुकसान

सड़न और संक्रमण: पेड़ के पास रखे भोजन के सड़ने से फंगल और बैक्टीरियल संक्रमण फैल सकते हैं, जो पेड़ की छाल और जड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

अन्य जीवों का आकर्षण: बचा हुआ खाना चूहों, गिलहरियों और पक्षियों को आकर्षित कर सकता है, जो पेड़ की पत्तियों और छाल को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

पूजा के दौरान सावधानियाँ

कृत्रिम वस्त्रों का उपयोग: पेड़ की जड़ों और तने के पास कृत्रिम वस्त्र या बर्तन का उपयोग करें ताकि कोई भी भोजन सीधे जमीन पर न गिरे।

जल का प्रयोग: पेड़ के पास केवल जल अर्पित करें, जिससे पेड़ को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचे और यह पर्यावरण के अनुकूल भी हो।

प्राकृतिक सामग्री का उपयोग:

यदि आप कुछ अर्पित करना चाहते हैं, तो फूल और पत्तियों का उपयोग करें, जो कि पेड़ के लिए हानिकारक नहीं हैं।

हमारी अपील

आइए, हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने पूजा और धार्मिक क्रियाकलापों में पेड़ों के प्रति सचेत रहेंगे। पीपल और बरगद जैसे पवित्र पेड़ों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए इन साधारण उपायों का पालन करें। याद रखें, हमारे छोटे-छोटे कदम पर्यावरण संरक्षण में बड़ा योगदान दे सकते हैं।

हाथ जोड़कर हम आपसे निवेदन करते हैं कि पेड़ों की रक्षा के इस प्रयास में हमारे साथ जुड़ें और उन्हें स्वस्थ और सुरक्षित बनाए रखें।

indiangreenbuddy@gmail.com

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)
TOLWA
website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com
रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण
रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

वाराणसी संसदीय क्षेत्र में वो सात लोग कौन हैं जो दे रहे हैं पीएम मोदी के चुनाव प्रचार को नई धार

प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में काम कर रही भाजपा की मुख्य टीम में शामिल सात सदस्यों की बात करें तो आपको बता दें कि इसमें प्रमुख नाम सुनील बंसल का है। वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भरोसेमंद लोगों में से एक हैं। सुनील बंसल पिछले कुछ महीनों से लगभग सारा समय वाराणसी में दे रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से लगातार तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं। देखा जाये तो वाराणसी में भाजपा उम्मीदवार के रूप में प्रधानमंत्री मोदी की जीत पर किसी को कोई संशय नहीं है लेकिन भाजपा का प्रयास है कि इस बार की जीत पहले से ज्यादा बड़े अंतर से होनी चाहिए। भाजपा ने बीस लाख के आसपास मतदाताओं की संख्या वाली वाराणसी सीट पर प्रधानमंत्री को 10 लाख से ज्यादा वोट दिलवाने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए पार्टी ने तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां बांट कर उन्हें काम पर लगा दिया है। भाजपा के स्थानीय विधायक, पार्षद तो छोटी-छोटी टोलियां बनाकर घर-घर संपर्क साध ही रहे हैं साथ ही जिन-जिन राज्यों में चुनाव हो चुके हैं वहां-वहां के भाजपा नेता और कार्यकर्ता भी वाराणसी आकर प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार में हाथ बंटा रहे हैं। हम आपको बता दें कि दूसरे राज्यों से आये प्रवासी कार्यकर्ताओं से समन्वय के लिए प्रधानमंत्री के केंद्रीय चुनाव कार्यालय में टीमें बना दी गयी हैं। दूसरे राज्यों से आये लोग वाराणसी में खासकर उन स्थानों पर जा रहे हैं जहां उनके राज्य के लोगों की बहुतायत है। जैसे महाराष्ट्र से आये कार्यकर्ता वाराणसी में मराठी इलाकों में जा रहे हैं, राजस्थान से आये कार्यकर्ता उन इलाकों में जा रहे हैं जहां राजस्थानी मूल के लोग रहते हैं। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में इस समय उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम के कार्यकर्ताओं का जो समागम हो रखा है वह देखते ही बनता है। प्रभासाक्षी ने अपनी चुनाव यात्रा के दौरान पाया कि प्रवासी कार्यकर्ताओं को काशी में पड़ रही भीषण गर्मी से जरा भी कष्ट नहीं हो रहा है और उनका प्रयास है कि प्रधानमंत्री की जीत देश में सबसे बड़ी जीत के रूप में दर्ज हो।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री ने अपने नामांकन से पहले भव्य रोड शो और उसके बाद हाल ही में स्त्री शक्ति के साथ संवाद कार्यक्रम के जरिये तो अपना प्रचार किया ही साथ ही प्रचार की हर गतिविधि पर खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी नजर रखे हुए हैं। चुनाव प्रचार में कहीं कोई कमी नहीं रह जाये इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार काशी का दौरा कर रहे हैं। भाजपा के कई केंद्रीय नेताओं, केंद्रीय मंत्रियों और उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को भी वाराणसी में प्रचार की जिम्मेदारी दी गयी है। इसके अलावा काशी की जनता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचार कर रही है। देखा जाये तो यहां कहने को तो कई उम्मीदवार मैदान में हैं लेकिन आपको सड़कों पर लगे होर्डिंगों और घरों पर लगे भाजपा के झंडों तथा प्रधानमंत्री की तस्वीर वाले स्टीकरों से पता चल जायेगा कि यहां का चुनावी मिजाज क्या है।

लेकिन आज वाराणसी में प्रचार की जो छटा दिखाई पड़ रही है उसके लिए एक टीम ने खास मेहनत की है। यह टीम पिछले कई महीनों से काशी में डटी हुई है और पर्दे के पीछे रहते हुए सारे चुनाव प्रचार अभियान का संचालन कर रही है। इस टीम में जो सात लोग शामिल हैं वह दिन भर आपको प्रधानमंत्री के केंद्रीय चुनाव कार्यालय में विभिन्न बैठकों के माध्यमों से प्रचार अभियान की समीक्षा करते, देशभर से आ रहे कार्यकर्ताओं से मिलने और प्रचार में कहीं किसी प्रकार की कमी ना रह जाये, इसकी चिंता करते हुए दिखेंगे। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार अभियान से जुड़े हर छोटे-बड़े काम को देख रही टीम में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य अश्विनी त्यागी और अरुण पाठक, गुजरात के पूर्व विधायक जगदीश पटेल, उत्तर प्रदेश के इटवा के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री सतीश द्विवेदी, उत्तर प्रदेश के रोहनिया के पूर्व विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह और वाराणसी के भाजपा जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा शामिल हैं।

हम आपको याद दिला दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 4.79 लाख वोटों से हराया था। देखा जाये तो यह अंतर बहुत बड़ा था लेकिन फिर भी यह जीत देश भर में दस सबसे बड़ी जीतों में दर्ज नहीं हो सकी थी इसलिए भाजपा की टीम इस बार जीत का ऐसा रिकॉर्ड कायम करने के लिए मेहनत कर रही है जिसको तोड़ना दूसरों के लिए कठिन चुनौती साबित हो। इसीलिए प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को वोटों में तब्दील करने और ज्यादा से ज्यादा मतदान कराने के लिए यह टीम बेहद सक्रिय है।

जहां तक प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में काम कर रही भाजपा की मुख्य टीम में शामिल सात सदस्यों की बात है तो आपको बता दें कि इसमें प्रमुख नाम सुनील बंसल का है। वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भरोसेमंद लोगों में से एक हैं। सुनील बंसल पिछले कुछ महीनों से लगभग सारा समय वाराणसी में दे रहे हैं। अश्विनी त्यागी की बात करें तो आपको बता दें कि वह वाराणसी में पार्टी की समन्वय गतिविधियों के प्रभारी हैं। अश्विनी त्यागी भाजपा की उत्तर प्रदेश इकाई के महासचिव हैं और पार्टी की पश्चिमी इकाई के क्षेत्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। अश्विनी त्यागी को आठ महीने पहले वाराणसी में काम संभालने के लिए लाया गया था। जहां तक जगदीश पटेल की बात है तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव प्रचार शुरू होने से दो महीने पहले गुजरात के पूर्व विधायक जगदीश पटेल को समन्वय और प्रबंधन से संबंधी कामकाज को देखने के लिए वाराणसी भेजा गया था। जगदीश पटेल 2019 में अमराईवाड़ी से उपचुनाव जीतकर विधायक बने थे। उन्होंने अहमदाबाद शहर अध्यक्ष के रूप में भी काम किया और मेहसाणा, भावनगर और पाटन जिलों के भाजपा प्रभारी के रूप में भी काम किया है। वह अमित शाह के भरोसेमंद व्यक्ति माने जाते हैं। वहीं सुरेंद्र नारायण सिंह की बात करें तो आपको बता दें कि वह वाराणसी जिले के रोहनिया से पूर्व विधायक हैं। इस क्षेत्र में कुर्मी और भूमिहार मतदाता बड़ी संख्या में रहते हैं। उल्लेखनीय है कि वाराणसी में कुर्मी जाति के 2 लाख मतदाता होने का अनुमान है। सुरेंद्र नारायण सिंह रैलियों और रोड शो से संबंधी कामकाज देखते हैं और चुनाव प्रचार संबंधी टीमों के साथ समन्वय करते हैं।

वहीं, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री सतीश द्विवेदी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली पहली भाजपा सरकार में शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। वह वाराणसी में मतदाताओं तक पहुंच बनाने और हर जाति की छोटी-छोटी बैठकें आयोजित करने का काम देख रहे हैं। वह वाराणसी क्षेत्र के ऐसे मतदाताओं से भी संपर्क साध रहे हैं जोकि समाज में प्रभावशाली छवि वाले हैं। उनका प्रयास है कि ऐसे मतदाताओं के माध्यम से समाज में ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए संदेश भेजा जाये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समूहों में जाकर मतदान करने का जो आह्वान किया है उसे सफल बनाने के लिए भी सतीश द्विवेदी दिन-रात काम कर रहे हैं।

इसी प्रकार तीसरी बार कानपुर से एमएलसी बने अरुण पाठक को पिछले साल वाराणसी जिले और शहर का प्रभारी बनाया गया था और वर्तमान में वह बूथ प्रबंधन का काम देख रहे हैं। उनकी जिम्मेदारियों में लाभार्थी सम्मेलन आयोजित करना, बूथ को मजबूत करना, पन्ना प्रमुखों की सूची तैयार करना, बूथ समितियों का समन्वय और बूथ के काम का जायजा लेना शामिल है। हम आपको बता दें कि वाराणसी में 1,909 बूथ हैं और इनमें से 150 बूथ भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण माने जाते हैं क्योंकि यहां अल्पसंख्यक समुदाय का दबदबा है और यह वर्ग भाजपा को अधिकांशतः वोट नहीं देता है। अरुण पाठक की जिम्मेदारी है कि जिन बूथों पर भाजपा को ज्यादा वोट नहीं मिलते हैं वहां पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट दिलाने के लिए काम करना है।

वहीं हंसराज विश्वकर्मा की बात करें तो वह वाराणसी जिला भाजपा अध्यक्ष के रूप में 2017 और 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों और 2019 के लोकसभा चुनावों की देखरेख कर चुके हैं। भूपेंद्र चौधरी जब उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बने तो उन्होंने पिछले साल अपनी नई टीम की जो घोषणा की थी उसमें हंसराज विश्वकर्मा को उनके पद पर बनाये रखा था। इस प्रकार, विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा 2016 से ही जिला भाजपा का अध्यक्ष पद संभाल रहे हैं जोकि बड़ी बात है। पिछड़े समुदायों पर अच्छी पकड़ रखने वाले हंसराज विश्वकर्मा के बारे में माना जाता है कि वह लगभग 3000 लोगों को तत्काल एकत्रित कर सकते हैं।

बहरहाल, अपनी स्थिति मजबूत होने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी अपने चुनाव में कोई चूक नहीं रहने देना चाहते इसलिए वह पार्टी कार्यकर्ताओं को बार-बार समझा रहे हैं कि जुलूस, नारे और रोड शो मतदान बूथों को प्रभावित नहीं करते हैं। अतः संकल्प हर मतदान केंद्र को जीतने का होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं को लक्ष्य दिया है कि हर मतदान केंद्र पर भाजपा को पिछली बार से 370 वोट अतिरिक्त दिलवाने का प्रयास करना है। प्रधानमंत्री का यह लक्ष्य हासिल हो सके इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह भी पूरे तौर पर सक्रिय हैं। उन्होंने अपने हालिया वाराणसी दौरे के दौरान पार्टी की एक बैठक में कहा था कि वह कार्यकर्ता जो अधिकतम मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर लाने में कामयाब होंगे, उन्हें चुनाव के बाद पुरस्कृत किया जायेगा। देखना होगा कि इस बार का परिणाम क्या रहता है।

अनियमित खाना खाने से सेहत और वजन पर पड़ सकता है बुरा असर, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट

ओवर ईटिंग करना और एक्सरसाइज न करना वेट बढ़ने का मुख्य कारण होता है। इसलिए खानपान की आदतों में सुधार करने के साथ ही डाइट में हेल्दी चीजों को शामिल करना चाहिए। अनियमित खाने का सेहत और वजन पर असर पड़ता है।

ओवर ईटिंग करना और एक्सरसाइज न करना वेट बढ़ने का मुख्य कारण होता है। इसलिए खानपान की आदतों में सुधार करने के साथ ही डाइट में हेल्दी चीजों को शामिल करना चाहिए। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो अनियमित खाना खाते हैं। इन लोगों के खाना खाने का समय फिक्स नहीं होता है। यहां तक की वेट लॉस की चाहत में मील्स को स्किप कर देते हैं। लेकिन यह जानना बेहद जरूरी है कि क्या सच में अनियमित खाना खाने से वेट कम हो सकता है।

वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो अनियमित खाना खाते हैं लेकिन इसके बाद भी उनका वेट कम होता है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या सही है। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या अनियमित खाने से वजन बढ़ सकता है या वजन कम किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं एक्सपर्ट की इस बारे में क्या राय है।

अनियमित खाना खाने से आपका वजन बढ़ सकता है और आपकी सेहत पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नियमित रूप से खाना खाने वाले लोगों का स्वास्थ्य बेहतर रहता है। साथ ही उनमें मोटापे की समस्या नहीं होती है। वहीं जो लोग अनियमित खाना खाते हैं, या लेट नाइट शिफ्ट के कारण देर रात खाना खाते हैं। वह लोग ओबेसिटी का शिकार ज्यादा होते हैं। जिन लोगों के खाना खाने का समय फिक्स नहीं होता है, उन्हें मोटापे और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

इतना ही नहीं जिन लोगों का खाना खाने का समय फिक्स नहीं होता है, उनके खानपान में कंसिसटेंसी की कमी होती है। इन लोगों का मेटाबॉलिज्म भी सही तरह से काम नहीं करता है। इन लोगों में बॉडी मास इंडेक्स भी हाई होता है। अगर आप इसको सरल शब्दों में समझना चाहें, तो ऐसे लोगों में हाई बॉडी फैट पाया जाता है। अनियमित खाना खाने की वजह से शरीर का फैट बढ़ सकता है, जोकि सही नहीं है।

न्यूट्रिएंट्स की कमी

वहीं अनियमित खाना खाने की वजह से लोग अक्सर भूखे ही रह जाते हैं। फिर भूख मिटाने के लिए स्नैक्स, जंक फूड और अनहेल्दी चीजों का सेवन करने लगते हैं। जिससे शरीर को पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है।

पाचन संबंधी समस्या

अगर आप भी अनियमित खाना खाते हैं, तो आपको पाचन संबंधी समस्या शुरू हो सकती है। दरअसल, सही समय पर और हेल्दी डाइट फॉलो नहीं करने पर यह आपकी पाचन क्रिया को प्रभावित करता है। इस तरह के लोगों में कब्ज की शिकायत होने लगती है।

ईटिंग डिसऑर्डर का शिकार

बता दें कि जो लोग अनियमित खाना खाते हैं या अक्सर खाना स्किप करते हैं। उन लोगों को एक समय के बाद ईटिंग डिसऑर्डर होता है। क्योंकि समय से खाना न खाने की वजह से भूख लगती रहती है। भूख को मिटाने के लिए ऐसे लोग अपने पास चिप्स और स्नैक्स आदि रखने लगते हैं। कई बार बिना भूख के भी इन चीजों का सेवन करते हैं। जिसके कारण वजन बढ़ने लगता है।

हर उम्र की महिलाएं फॉलो कर सकती हैं ये 7 दिन का योगा प्लान, खत्म होगी जिद्दी चर्बी

यदि आप अपनी डेली रूटीन में प्राणायाम और योगासन को शामिल करती हैं, तो तनाव, डिप्रेशन और घबराहट कम करने में सहायता मिलती है। योग हार्मोन्स को बैलेंस करता है, जिससे प्रजनन स्वास्थ्य को भी फायदा मिलता है।

कई लोगों का मानना होता है कि योग सिर्फ व्यायाम है। लेकिन आपको बता दें कि योग महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं। क्योंकि यह न सिर्फ आपको शारीरिक तौर पर बल्कि मानसिक और भावनात्मक तौर पर भी मजबूती देता है। रोजाना योग करने से व्यक्ति सेहतमंद बना रहता है। इससे मसल्स मजबूत होती हैं और शरीर लचीला बनता है। वहीं महिलाओं को पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द से भी राहत मिलती है।

वहीं आजकल की जिंदगी में हर किसी को तनाव होता है। वहीं यदि आप अपनी डेली रूटीन में प्राणायाम और योगासन को शामिल करती हैं, तो तनाव, डिप्रेशन और घबराहट कम करने में सहायता मिलती है। योग हार्मोन्स को बैलेंस करता है, जिससे प्रजनन स्वास्थ्य को भी फायदा मिलता है। इससे पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है और शरीर को आसानी से पोषक तत्व मिलते हैं। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको सात दिन का आसान योग प्लान बताने जा रहे हैं, जो लगभग हर महिला की उम्र को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

पहला दिन

पहले दिन की शुरूआत सूर्योदय के साथ हठ योग से करें। इस दौरान गहरी सांस लेते हुए शरीर को हल्का स्ट्रेच करें।

रात को सोने से पहले विपरीत करणी, सेतुबंधासन और बालासन कर तनाव को दूर कर आरामदायक नींद पाएं।

दूसरा दिन

सूर्य नमस्कार कर अपने शरीर को वॉर्मअप करें। इसके बाद नौकासन, प्लैंक और डॉल्फिन प्लैंक जैसे पोज करें। इससे आपके मसल्स की मजबूती बढ़ेगी।

इसके बाद शाम को कपालभाति और अनुलोम-विलोम जैसी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। इससे आपका मन शांत होगा और तनाव कम होगा।

तीसरा दिन

तीसरे दिन की शुरूआत विन्यास योग से करनी चाहिए। इस आसन को करने के दौरान सांसों और आसन को मिलाते हुए विभिन्न गतिविधियां की जाती हैं। इससे आपका शरीर लचीला होने के साथ संतुलित होता है। आप त्रिकोणासन, वीरभद्रासन और वृक्षासन का भी अभ्यास कर सकती हैं।

वहीं शाम के समय यिन योग या हल्के स्ट्रेच कर मांसपेशियों की अकड़न को कम करें और अपने जोड़ों को लचीला बनाएं। इस दौरान बटरफ्लाई, ड्रैगन और कैटरपिलर जैसे आसनों में ज्यादा से ज्यादा रुकने का प्रयास करें।

चौथा दिन

चौथे दिन की शुरूआत यिन-यांग योग से करना चाहिए। इस आसन में एक्टिव पोज और पैसिव स्ट्रेच को मिलाया जाता है, जो शरीर की एनर्जी को बैलेंस कर शरीर को आराम देता है।

वहीं शाम को ध्यान लगाने और मन को शांत रखने के लिए कुछ समय निकालें। शुरूआत में बैठकर सिर्फ ध्यान करें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। ध्यान लगाने से न सिर्फ आंतरिक शांति बल्कि करुणा की भावना भी पैदा होती है।

पांचवां दिन

इस दिन पावर योग का अभ्यास कर शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाएं। इससे सहनशक्ति बढ़ेगी। इस दिन चेयर पोज से लेकर क्रिसेंट लंज और अधोमुखश्वानासन जैसी डायनेमिक सीक्वेंस को एड करें।

फिर रात को सोने से पहले योग निद्रा या गाइडेड रिलैक्सेशन प्रैक्टिस करनी चाहिए। जिससे कि आपका शरीर और दिमाग रिलैक्स फील कर अच्छी नींद आ सके।

छठा दिन

छठे दिन की शुरूआत भुजंगासन, सेतुबंधासन और बितिलासन जैसे आसनों से करनी चाहिए। इससे पीठ की मांसपेशियां और रीढ़ की हड्डी को मजबूती मिलती है और कमर दर्द में राहत मिलती है। साथ ही आपके शरीर का पोस्चर भी ठीक रहता है।

रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाने और तनाव को कम करने के लिए अर्द्ध मत्स्येंद्रासन और पश्चिमोत्तानासन करना चाहिए।

सातवां दिन

वहीं सप्ताह के आखिरी दिन शरीर को मजबूत और लचीला बनाने के लिए विभिन्न आसनों का अभ्यास करना चाहिए। इस दिन आप बैठकर किए जाने वाले स्ट्रेच और उल्टे होकर किए जाने वाले आसन और खड़े होकर संतुलन बनाने वाले आसन कर सकती हैं। इससे आपका दिमाग भी चुस्त रहता है।

सप्ताह के आखिरी दिन आभार और कृतज्ञता के साथ मेडिटेशन करें। पूरे सप्ताह के अनुभवों को डायरी में मेटेंन करने के साथ ही सेल्फ केयर व ग्रोथ पर ध्यान दें।

सिंपल सी प्रिंटेड साड़ी में चाहिए स्टाइलिश लुक, तो इन अभिनेत्रियों के लुक से लें इंस्पिरेशन

आप भी अपनी बॉडी शेप के मुताबिक प्रिंटेड साड़ी को कैरी कर स्टाइलिश और आरामदायक लुक पा सकती हैं। अगर आप भी प्रिंटेड साड़ी में खुद को परफेक्ट लुक देना चाहती हैं, तो इन एक्ट्रेस के प्रिंटेड साड़ियो से कुछ टिप्स ले सकती हैं।

साड़ी एक ऐसा आउटफिट है, जो हमेशा फैशन के साथ चलता है। साड़ियों में आपको कई तरह के स्टाइल, वैरायटी और फैशन ट्रेंड देखने को मिलते हैं। सर्दियों से लेकर गर्मियों तक के लिए साड़ियों में कई अलग-अलग ऑप्शन देखने को मिलते हैं। वहीं साड़ियों के फेब्रिक से लेकर रंग और प्रिंट में भी कई तरह की वैरायटी होती हैं। भारतीय महिलाओं में साड़ी को लेकर अलग तरह का क्रेज देखने को मिलता है। समय-समय पर साड़ी को स्टाइल करने का नया फैशन ट्रेंड भी देखने को मिलता है।

बता दें कि आजकल प्रिंटेड साड़ियों का क्रेज एक बार फिर देखने को मिल रहा है। आम महिलाओं से लेकर बॉलीवुड अभिनेत्रियों को कई मौके पर प्रिंटेड साड़ी पहने देखा जाता है। साड़ी में जॉर्जेट, शिफॉन और अन्य कई फैब्रिक में प्रिंट मिलते हैं। ऐसे में आप भी अपनी बॉडी शेप के मुताबिक प्रिंटेड साड़ी को कैरी कर स्टाइलिश और आरामदायक लुक पा सकती हैं। अगर आप भी प्रिंटेड साड़ी में खुद को परफेक्ट लुक देना चाहती हैं, तो इन एक्ट्रेस के प्रिंटेड साड़ियो से कुछ टिप्स ले सकती हैं।

विद्या बालन की प्रिंटेड साड़ी

अगर आप भी प्रिंटेड साड़ी में विद्या बालन जैसा लुक पाना चाहती हैं, तो एक्ट्रेस के इस लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं। विद्या बालन के पास साड़ियों का काफी शानदार कलेक्शन है। क्योंकि उनको कई मौकों पर साधारण प्रिंटेड साड़ी को स्टाइलिश तरीके से पहने देखा जा चुका है। यहां पर एक्ट्रेस ने काले रंग की प्रिंटेड साड़ी कैरी की है। बेस्पोक प्रिंट की साफिया सिल्क फैब्रिक साड़ी में ऑफ-व्हाइट और गोल्डन रंग का कॉम्बिनेशन है। इस साड़ी में मरून रंग का डबल शेड रेशम बॉर्डर है। वहीं अपने लुक को परफेक्ट बनाने के लिए एक्ट्रेस ने हाफ स्लीव रेड प्रिंटेड ब्लाउज कैरी किया है।

हिना खान की प्रिंटेड साड़ी

एक्ट्रेस हिना खान अक्सर अपने लुक्स को लेकर सुर्खियां बटोरती हैं। हिना ने जॉर्जेट की ब्लैक एंड व्हाइट साड़ी को बेहद स्टाइलिश तरीके से कैरी किया है। उनकी इस सिंपल सी साड़ी पर ब्लैक चेक या बॉक्स बने हैं। वहीं हिना खान के लुक को डिजाइन ब्लाउज आकर्षक बना रहा है। उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट पेप्लम ब्लाउज पहना है। इसमें जरदोजी कढ़ाई की गई है। चोली वाले हिस्से में कढ़ाई है और ब्लाउज का डिजाइन फ्रंट स्लिट स्टाइल में है।

जान्हवी कपूर की प्रिंटेड साड़ी

बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकार जान्हवी कपूर की तरह आप भी प्रिंटेड साड़ी को अपने वार्डरोब का हिस्सा बना सकती हैं। बता दें कि इन दिनों फ्लोरल प्रिंट काफी ज्यादा ट्रेंड में है। वहीं वेस्टर्न से ट्रेडिशनल फ्लोरल प्रिंट आउटफिट में एक्ट्रेस काफी खूबसूरत लग रही हैं। एक्ट्रेस ने फ्लोरल प्रिंटेड शियर साड़ी पहनी है। इस साड़ी पर ऑर्गेंजा साड़ी पर लाल, गुलाबी और पीले रंग के गुलाब के प्रिंट बने हैं। वहीं इस साड़ी पर सिल्वर पट्टी बॉर्डर दिया गया है।

उर्फी जावेद की प्रिंटेड साड़ी

उर्फी जावेद अपने बोल्ड आउटफिट और अतरंगी फैशन के कारण जानी जाती हैं। वहीं एक्ट्रेस प्रिंटेड साड़ियों के साथ कई बार एक्सपेरिमेंट भी कर चुकी हैं। उन्होंने मुस्लिन कॉटन की साड़ी पहनी है, इस पीले रंग की साड़ी में काले रंग के प्रिंट बने हैं। वहीं एक्ट्रेस का साड़ी ड्रेप करने का तरीका भी बोल्ड है। उन्होंने इस साड़ी के साथ ब्लैक ब्रालेट कैरी किया है।

दिल्ली में रात 9 बजे तक 55.58 प्रतिशत मतदान, उत्तर-पूर्वी में सबसे ज्यादा तो इस सीट पर पड़े सबसे कम वोट

दिल्ली के कई मतदान केंद्रों पर निर्धारित समय तक पहुंचकर लाइन में लगे मतदाताओं का शाम छह बजे के बाद भी देर रात तक मतदान की प्रक्रिया जारी थी। चुनाव आयोग के वोटर टर्न आउट एप के अनुसार रात करीब नौ बजे तक दिल्ली में 55.58 प्रतिशत मतदान हुआ। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह मतदान का फाइनल डाटा नहीं है। मतदान का अंतिम डाटा बाद में जारी होगा।

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो गया। यहां के सात लोकसभा सीटों के लिए 2627 मतदान स्थलों के 13,641 मतदान केंद्रों पर हुए मतदान में कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर ईवीएम में खराबी और मतदान प्रभावित होने की भी खास घटनाएं सामने नहीं आई। 43.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच हुए इस चुनाव में दिल्ली के मतदाताओं का जोश कम नहीं हुआ। इस वजह से इस बार के लोकसभा चुनाव में भी पिछले लोकसभा चुनाव के मतदान होने की सूचना है।

दिल्ली में सुबह सात से शाम सात बजे तक मतदान का समय था। चुनाव आयोग के अनुसार शाम छह बजे तक दिल्ली में 54.37 प्रतिशत मतदान हुआ। कई मतदान केंद्रों पर निर्धारित समय तक पहुंचकर लाइन में लगे मतदाताओं का शाम छह बजे के बाद भी देर रात तक मतदान की प्रक्रिया जारी थी।

चुनाव आयोग के वोटर टर्न आउट एप के अनुसार रात करीब नौ बजे तक दिल्ली में 55.58 प्रतिशत मतदान हुआ। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह मतदान का फाइनल डाटा नहीं है। मतदान का अंतिम डाटा बाद में जारी होगा।

आंकड़ों के अनुसार 4.92 प्रतिशत मतदान कम

दिल्ली में पिछले लोकसभा चुनाव में 60.50 प्रतिशत मतदान हुआ था। इसके मुकाबले वोटर टर्न आउट एप पर रात नौ बजे तक प्रदर्शित मतदान के आंकड़ों के अनुसार 4.92 प्रतिशत मतदान कम है, लेकिन सीईओ कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में मतदान का आंकड़ा 59 प्रतिशत से अधिक पहुंच चुका है, जो वोटर टर्न आउट एप पर अपडेट नहीं हुआ है। फाइनल डाटा अपडेट होने पर उम्मीद है कि पिछले लोकसभा चुनाव में हुए मतदान के आसपास ही इस बार भी मतदान कुल प्रतिशत रहेगा।

बहरहाल, दिल्ली में सबसे अधिक मतदान उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र (60.84 प्रतिशत) में हुआ है। नई दिल्ली इलाके में मतदान वोट देने के लिए कम निकलने। इस वजह से नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में सबसे कम 51.98 प्रतिशत मतदान हुआ है। यह डाटा भी अभी बाद में अपडेट होगा।

युवा मतदाताओं में भी दिखा उत्साह

दिल्ली में एक करोड़ 52 लाख एक हजार 936 मतदाता हैं। जिसमें से पुरुष मतदाता 82 लाख 12 हजार 794 हैं। इसके अलावा 69 लाख 87 हजार 914 महिला मतदाता व 1228 थर्ड जेंडर हैं। वहीं दो लाख 52 हजार 38 फर्स्ट टाइम वोटर थे। 18 से 19 वर्ष के इन युवा मतदाताओं में भी मतदान के लिए उत्साह देखा गया।

वर्ष 2019 में पिछला लोकसभा चुनाव 12 मई को हुआ था। तब दिल्ली में 39 डिग्री सेल्सियस तापमान था, जो सामान्य था। पिछली बार के मुकाबले 4.4 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिक होने के बावजूद इस बार मतदान पर ज्यादा असर नहीं पड़ा है।

दिल्ली की सातों लोकसभा क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत

लोकसभा क्षेत्र	मतदान का प्रतिशत
चांदनी चौक	57.39 प्रतिशत
पूर्वी दिल्ली	54.79 प्रतिशत
नई दिल्ली	51.98 प्रतिशत
उत्तरी पूर्वी दिल्ली	60.84 प्रतिशत
उत्तरी पश्चिमी दिल्ली	53.81 प्रतिशत
दक्षिणी दिल्ली	53.86 प्रतिशत
पश्चिमी दिल्ली	57.51 प्रतिशत

दिल्ली में 7 सीटों पर काटती धूप के बीच बंपर वोटिंग

परिवहन विशेष। एसडी सेठी।

छठे चरण में दिल्ली की सातों लोकसभा सीटों पर चिलचिलाती धूप, गर्मी से बेहाली के बावजूद जैसे तैसे मतदान संपन्न हो गया। शाम 5 बजे तक का वोट प्रतिशत करीब 53.73 फीसदी पड चुका था।अभी अंतिम वोट प्रतिशत आंकडे का इंतजार है। लोगों में मतदान करने का करेज इस हद तक था कि , सुबह सवेरे 7 बजे से लोगों में ईवीएम का बटन दबाने की होड मची रही। ये मतदान डालने का उत्साह शाम 6 बजे तक यूं ही बना रहा। इस बीच हालांकि वोटर्स ने भी प्रशासन की ओर से खासी खामियां भी गिनाई। मतदाताओ का कहना था कि गर्मी ओर चिलचिलाती धूप में मतदान केंद्र तक पहुंच पाना आसान नहीं रहा। बिमार, उम्रदराज,तक केंद्र के बाहर धूम में लम्बी लाइन भूखे प्यासे खडा रहना पडा।इतनी गर्मी के बावजूद प्रशासन की ओर से शीतल जल तक का इंतजाम नहीं किया गया था। गोदियो में छोटे बच्चे और ऊंगलियो को थामें बडे बच्चे प्यास के मारे परेशान दिखाई दिए। बावजूद इसके वोटर्स का उत्साह बरकरार था।

मतदाताओ का आरोप था कि छत पर रखी पानी की टंकी से उबलते पानी से ही गला तर करने को मजबूर मतदाता प्रशासन को कोसते नजर आए। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक मतदाताओ के आने का सिलसिला जारी रहा। शाम 5:00 बजे तक दिल्ली में 53.77 फीसदी वोट डाले जा चुके थे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने परिवार के साथ सिविल लाइन बूथ पर अपने वोट डाले। उनका लोकसभा क्षेत्र चांदनी चौक में पडता है। 85 वर्षीय पिता का हाथ थामें केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ बाकायदा लाइन में लगे ओर अपनी बारी पर वोट डाला। इसी तरह नई दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्यक्षी सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज ने भी वोट डाला। बहरहाल दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गए थे। पुलिस बाकायदा ड्रोन के जरिए मतदान केंद्र के अंदर और बाहर पूरी चौकसी रख रहे थे। राजधानी दिल्ली से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। मतदान बेहद शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। सबसे ज्यादा उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट जहां से भाजपा के प्रत्यक्षी मनोज तिवारी के साथ कांग्रेस के कन्हैया कुमार के बीच तगडा मुकाबला देखने को मिला। दोनों ओर से मतदाताओ का रेला-का रेला केंद्र की ओर शाम तक भीडभाड देखी गई। इसके अलावा नोर्थ वेस्ट लोकसभा सीट से भाजपा के योगेन्द्र चंदौलिया और कांग्रेस के उदित राज के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। टेबिल पर उदित राज के कार्यकर्ताओ जिनमें आम आदमी के कार्यकरता समेत कांगेस के कार्यकर्ता मतदाताओं बीच घिरे दिखाई दिये। वहीं बूथ नंबर 232 पर भाजपा का कोई टेबल दिखाई नहीं दिया। लगता है उन्होंने मान लिया था कि बिना हाथ पैर हिलाए ही चार सौ पार की नैया को किनारे लगा लेगें।बहरहाल अब तो तमाम सातों लोकसभा सीटों के प्रत्यक्षियों का भाग्य ईवीएम में बंद हो चुका है। अब 1 जून को सातवें चरण का चक्र पूरा होने के बाद 4 जून को तमाम 543 लोकसभा सीटों के परिणाम भी आ जाएगे। तब तक तमाम प्रत्यक्षियो की बेचैनी बनी रहने वाली है।

मुस्लिमों ने जमकर किया मतदान, फिर भी पिछले चुनाव के मुकाबले पिछड़े; जानें दिल्लीवासियों ने क्या कहा

दिल्ली में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारे लगनी शुरू हो गई थीं। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार चुनाव में मुस्लिम इलाकों में मतदान कम हुआ। मतदान प्रतिशत में पिछड़ने की वजह गर्मी को माना जा रहा है। कम मतदान होने से किसको घाटा हुआ और किसको फायदा मिलेगा यह चार जून को परिणाम आने पर पता चलेगा।

पूर्वी दिल्ली। इस लोकसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों की नजरें मुस्लिम मतदाताओं पर टिकी रहीं। आप और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा है। शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारे लगनी शुरू हो गई थीं। बुजुर्गों से लेकर बुर्का पहने महिलाओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा था। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार चुनाव में मुस्लिम इलाकों में मतदान कम हुआ। मतदान प्रतिशत में पिछड़ने की वजह गर्मी को माना जा रहा है। कम मतदान होने से किसको घाटा हुआ और किसको फायदा मिलेगा, यह चार जून को परिणाम आने पर पता चलेगा।

मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र

विधानसभा क्षेत्र	मतदान प्रतिशत 2024	मतदान प्रतिशत 2019
मुस्तफाबाद	61.92	65.24
सीलमपुर	59.73	66.92
ओखला	51.04	52.75
बल्लीमरान	56.14	68.29
मटिया महल	58.46	67.12

नोट : चुनाव का आंकड़ा चुनाव आयोग के एप से लिया गया है।

'अब विकास के नाम पर वोट नहीं करती दिल्ली', PM मोदी की तारीफ के बाद अब LG सक्सेना के पक्ष में उतरे संदीप दीक्षित

कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा तासीर तो हमेशा बदलती रहती है दिल्ली में कभी किसी तीसरी पार्टी के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी लेकिन आज दिल्ली में वह भी है। दिल्ली में हमेशा कांग्रेस और भाजपा के बीच खींचतान बनी रहती थी। इसी तरह दिल्ली के मतदाताओं की प्रोफाइल भी बदल गई दिल्ली पहले हमेशा विकास पर वोट करती थी कभी लालच पर वोट नहीं करती थी

नई दिल्ली। बेशक दिल्ली में आप और कांग्रेस गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन इससे पूर्व सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित इससे खुश नहीं लगते। शुक्रवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तारीफ की तो शनिवार को वह एलजी वीके सक्सेना के साथ खड़े नजर आए।

दीक्षित ने कहा कि पहले दिल्ली के लोग विकास के लिए वोट डालते थे, लेकिन अब लालच के लिए वोट करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने आप द्वारा एलजी पर धीमी वोटिंग कराने संबंधी लगाए गए आरोपों पर भी उनका बचाव किया। उन्होंने कहा कि वोटिंग धीमी हो या तेज होना चुनाव की रणनीति पर निर्भर करता है।

तासीर हमेशा बदलती रहती है: संदीप दीक्षित

संदीप दीक्षित ने कहा, "तासीर तो हमेशा बदलती रहती है, दिल्ली में कभी किसी तीसरी पार्टी के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन आज दिल्ली में वह भी है। दिल्ली में हमेशा कांग्रेस और भाजपा के बीच खींचतान बनी रहती थी, लेकिन वो तासीर भी बदली और तीसरी पार्टी आ गई। इसी तरह दिल्ली के मतदाताओं की प्रोफाइल भी बदल गई, दिल्ली पहले हमेशा विकास पर वोट करती थी, कभी लालच पर वोट नहीं करती थी, लेकिन अब दिल्ली लालच पर वोट करती है, विकास पर वोट नहीं करती।

उंगली उठाने का कोई मतलब नहीं: संदीप दीक्षित

संदीप ने मतदान के तेज या धीमे होने की वजह भी बताई। उन्होंने कहा, "ये चुनाव की रणनीति होती है, आपके जो पोलिंग एजेंट होते हैं, उन पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर आपके पोलिंग एजेंट मुस्तैदी से बैठेंगे तो तेजी से वोटिंग होती है। इसमें किसी और पर उंगली उठाने का कोई मतलब नहीं है। ये चुनाव की रणनीति की बातें हैं।"

एलजी साहब ने जो कहा, वो सही है: संदीप दीक्षित

उन्होंने कहा, "जैसे मैं अभी एक बूथ पर गया था, वहां भाजपा का जो पोलिंग एजेंट था वो सरकारी एजेंटों के साथ बैठा हुआ था, जिससे मतदान धीमा हो रहा था। हमने उसको अलग करवाया। इसके बाद सरकारी ने अलग काम शुरू किया, पार्टी के पोलिंग एजेंट्स अलग हो गए, अपने आप मतदान तेज हो गया। इसलिए मैं मानूंगा कि एलजी साहब ने जो कहा है कि वो सही है कि इसे लेकर कोई शिकायत ना करे।

उन्होंने कहा कि बात ये है कि हमारे जो पोलिंग एजेंट होते हैं, बाहर उनके रिलिवर होते हैं, उनके पास बहुत अधिकार होते हैं। अगर किसी भी कारण से पोलिंग धीमी हो रही हो, चाहे रणनीति के तहत धीमी कर रहे हों या ऐसे ही धीमी हो रही हो तो वे उसे तेज करवा सकते हैं।"

दिल्ली के पास इस एक्सप्रेस-वे पर दौड़ती है मौत, जानिए ऐसा क्यों?

प्रदेश के पहले एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस-वे (यमुना एक्सप्रेस-वे) पर मथुरा से गौतमबुद्ध नगर तक ओवर लोड ट्रैक्टर ट्रॉली के रूप में मौत दौड़ती है। मथुरा व अलीगढ़ जिले से ईंट से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली एक्सप्रेस-वे पर रास्ते गौतमबुद्ध नगर तक आते हैं। रास्ते में जेवर टोल प्लाजा को क्रॉस करते हैं। यातायात पुलिस इन ओवर लोड ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकने में पूरी तरह से नाकाम है।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा। प्रदेश के पहले एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस-वे (यमुना एक्सप्रेस-वे) पर मथुरा से गौतमबुद्ध नगर तक ओवर लोड ट्रैक्टर ट्रॉली के रूप में मौत दौड़ती है। मथुरा व अलीगढ़ जिले से ईंट से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली एक्सप्रेस-वे पर रास्ते गौतमबुद्ध नगर तक आते हैं। रास्ते में जेवर टोल प्लाजा को क्रॉस करते हैं। लेकिन एक्सप्रेस-वे पर संचालन कर रही कंपनी जेपी इंफ्राटेक से लेकर यातायात पुलिस इन ओवर लोड ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकने में पूरी तरह से नाकाम है।

यमुना एक्सप्रेस-वे पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा 100 किमी प्रति घंटा निर्धारित की गई। लेकिन तेज गति से दौड़ते वाहनों के लिए एक्सप्रेस-वे पर गुजरने वाले धीमी गति वाहन हादसे का बड़ा कारण बन गए हैं।

इसका खामियाजा तेज गति वाहनों में सवार लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तेज गति व धीमी गति वाहनों के टकराने के एक्सप्रेस-वे पर कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।

एक्सेस कंट्रोल व कैमरों की निगरानी भी फेल

यमुना एक्सप्रेस-वे एक्सेस कंट्रोल है, एक्सप्रेस-वे पर कैमरे लगे हैं। आइआइटी दिल्ली के सुझाव पर कैमरों की संख्या को बढ़ाकर दोगुना भी हुई है, लेकिन यह यवस्था एक्सप्रेस-वे पर धड़ल्ले से दौड़ते ओवर लोड व धीमी गति वाहनों के सामने फेल है। एक्सप्रेस-वे से प्रतिदिन 200 से 250 ओवर लोड ट्रैक्टर ट्रॉली ईंट लेकर गुजरते हैं।

गौतमबुद्ध नगर में ईंट की मांग पूरी करने के लिए मथुरा अलीगढ़ से आती हैं ट्रैक्टर ट्रॉली

गौतमबुद्ध नगर में निर्माण कार्य बड़े पैमाने पर हो रहा है। ईंट की मांग काफी अधिक है, लेकिन जिले में जमीनों के अधिगृहीत होने व ईंट भट्ठों के बंद होने के कारण यह मांग पूरी नहीं हो पाती। जिले में 70 के करीब भट्ठे हैं। प्रदूषण को देखते हुए एनटीजी ने इनके संचालन पर रोक लगा दी थी। जिगजैग तकनीकी आधारित करीब पचास भट्ठों को बंद में संचालन की अनुमति दी गई, लेकिन जिले में ईंट की मांग को देखते हुए यह नाकाफी है। इसके अतिरिक्त यहां ईंट की कीमत भी अधिक है।

इसलिए मथुरा के बाजना, अलीगढ़ के टप्पल क्षेत्र से बड़े पैमाने पर जिले में ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिये ईंट जाती है। इसकी कीमत भी अपेक्षाकृत कम होती है। जिले के सापेक्ष करीब एक से डेढ़ हजार रुपये की बचत होती है।

एक्सप्रेस-वे पर रजिस्टर्ड ट्रैक्टर ट्रॉली का संचालन मान्य है। ओवर लोड वाहनों पर कार्रवाई यातायात पुलिस करती है। शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक ट्रैक्टर ट्रॉली का एक्सप्रेस-वे पर संचालन पर रोक है।

-जेके शर्मा, प्रबंधक जेवर टोल प्लाजा

एक्सप्रेस-वे पर कामर्शियल कार्यों में शामिल ट्रैक्टर ट्रॉली व धीमी गति वाहनों का संचालन रोकने के निर्देश दिए गए हैं। एक्सप्रेस-वे संचालन कर रही कंपनी को पत्र भेजा गया है। एक्सप्रेस-वे पर हादसों को रोकने के लिए आईआईटी दिल्ली के सुझावों को पूरी तरह से अपनाया गया है।

-डॉ. अरुणवीर सिंह, सीईओ यमुना प्राधिकरण

यमुना एक्सप्रेस-वे पर प्रतिबंधित वाहनों के खिलाफ नियमित कार्रवाई होती है। उनके चालान काटे जाते हैं। प्रतिबंधित वाहनों को प्रवेश बिंदुओं पर ही रोकने की जरूरत है।

-अनिल यादव, डीसीपी ट्रैफिक

हमारे देश के प्रिय युवाओं,

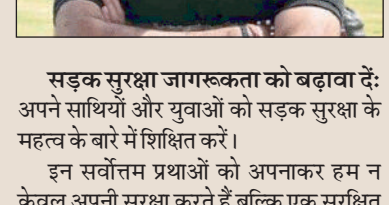

आज, मैं आपको अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे - सड़क सुरक्षा - के बारे में लिख रहा हूँ। यह केवल चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि सड़क पर सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाकर सुरक्षित रहने और अपने देश की सेवा करने की एक कला है। आप में से प्रत्येक व्यक्ति न केवल अपने जीवन पर, बल्कि अनगिनत अन्य लोगों के जीवन पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की शक्ति रखता है।

सड़क सुरक्षा एक सामूहिक जिम्मेदारी है। हर बार जब हम सड़क पर निकलते हैं, तो हमें अपने कार्यों और उनके संभावित परिणामों के प्रति सचेत रहना चाहिए। एक दुर्घटना केवल इसमें शामिल व्यक्तियों को ही प्रभावित नहीं करती; यह पूरे परिवार, समुदाय और पूरे समाज में हलचल पैदा करता है। इसके बाद होने वाला नुकसान, दर्द और कष्ट विनाशकारी और लंबे समय तक चलने वाला हो सकता है।

इन त्रासदियों को रोकने के लिए, हमें सुरक्षित व्यवहार अपनाना और अपनाना होगा:

यातायात नियमों का पालन करें: यातायात नियम हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। गति सीमा, यातायात संकेतों और सड़क संकेतों का पालन करना महत्वपूर्ण है।

ध्यान भटकाने से बचें: मोबाइल फोन जैसी ध्यान भटकाने वाली चीजें घातक हो सकती हैं। वाहन चलाते समय अपना ध्यान सड़क पर रखें।

कभी भी प्रभाव में गाड़ी न चलाएँ: शराब और नशीले पदार्थ निर्णय लेने और प्रतिक्रिया करने के समय को ख़राब करते हैं। कभी भी नशे में गाड़ी न चलाएं।

सीट बेल्ट और हेलमेट पहनें: ये सरल उपाय जान बचा सकते हैं। कार में सीट बेल्ट और दोपहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनें।

सड़क सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा दें: अपने साथियों और युवाओं को सड़क सुरक्षा के महत्व के बारे में शिक्षित करें।

इन सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाकर हम न केवल अपनी सुरक्षा करते हैं बल्कि एक सुरक्षित समाज में भी योगदान देते हैं। सड़क पर आपके कार्य दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं और जिम्मेदार व्यवहार के लिए एक मानक स्थापित कर सकते हैं। याद रखें, सड़क पर सुरक्षित रहना केवल नियमों का पालन करना नहीं है; यह आपके जीवन और दूसरों के जीवन की देखभाल के बारे में है।

साथ मिलकर, हम सकारात्मक बदलाव का एक प्रभावशाली प्रभाव पैदा कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारी सड़कें सभी के लिए सुरक्षित हैं। आइए हम सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता और दैनिक अभ्यास बनाने का संकल्प लें।

सुरक्षित रहें, जिम्मेदारी से गाड़ी चलाएं और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें।

शुभकामनाएं,

डॉ अंकुर शरण
राष्ट्रीय मुख्य परिवहन एवं योजना अधिकारी
Road Safety Omni

44 डिग्री की तपिश में भी ठंडा नहीं हुआ वोट का जोश, मतदान करके मन को मिला सुकून

गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में कुल 25 .73 लाख मतदाता हैं प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने के लिए सेक्टर-14 कॉलेज में बसों की व्यवस्था की गई है। 7 हजार कर्मचारी मतदान कराएंगे। 19 क्यूआरटी टीम 12 एसएसटी 20 एफएसटी फील्ड में तैनात किए गए हैं। 2014 में 71.58 प्रतिशत वोटिंग कर मतदाताओं ने 1977 के आंकड़े को छूने की कोशिश की।

गुरुग्राम। मई में ही धरती जून जैसी तप रही है। गुड़गांव लोकसभा के लिए मतदान के दिन शनिवार सुबह 11 बजे ही तापमान 40.0 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। दोपहर होते ही आसमान से आग बरसने लगी। असहनीय गर्मी के बावजूद वोट डालने के लिए लोग कतार में खड़े रहे।

कई बूथों पर तो दोपहर में तीन बजे भी मतदाताओं की लंबी लाइन नजर आई। प्रशासन ने टेंट आदि लगाकर धूप से बचाव के भी प्रबंध किए थे। मौसम विभाग के अनुसार, न्यूनतम तापमान 29.7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 44.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

रातें भी गुजर रहीं गर्म

मौसम विभाग ने हीट वेव (लू) और तापमान बढ़ने की चेतावनी जारी की थी। आने वाले दिनों में भी झुलसाने वाली गर्मी से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। पिछले 15 दिनों से रातें भी ठंडी नहीं हो रही हैं। पिछले सप्ताह दिन का पारा 45.0 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया था और आगामी दिनों में अधिकतम तापमान 47.0 डिग्री सेल्सियस तक या इससे भी ऊपर पहुंच सकता है।

45 डिग्री से पार भी पहुंचा था पारा

पिछले वर्षों की अगर बात करें तो वर्ष 2022 में 16 मई को अधिकतम तापमान 47.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। 2023 में मई महीना बीच-बीच में हुई वर्षा की फुहारों के मौसम ज्यादा गरम नहीं रहा और इस महीने में सबसे अधिक तापमान 23 मई को 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गत 19 मई को अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था।

एसी कमरों में बैठने वाले चिलचिलाती धूप में वोट डालने पहुंचे

आज 46 डिग्री तापमान की चिलचिलाती और झुलसा देन वाली धूप भी नही रोक पाई मतदाताओं के कदम लोकसभा चुनाव के इस लोकतंत्र की ईंट मजबूत करने लिए एयरकंडीशनर कमरों में बैठने वाले डीएलएफ वासियों ने वोटिंग करने में कोई कोर कसर नहीं छोड रहे हैं। डीएलएफ फेज एक से पांच के बूथों पर लोगों की लाइनें को देखते हुए अब पुराने गुरुग्राम और नए गुरुग्राम में मतदाताओं के घरों से निकलने में कोई फर्क नही रह गया हैं। लोग अपने मताधिकार के प्रयोग को लेकर जागरूक, उत्साहित और लहलायित नजर आए। बूथों पर पहली बार मतदाताओं के चेहरों पर उत्साह नजर आया।

निगम सड़कों पर कर रहा पानी का छिड़काव

भीषण गर्मी में सड़कें तेजी से गरम हो रही हैं। नगर निगम गुरुग्राम तापमान को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न सड़कों पर टैंकरों के माध्यम से एसटीपी के शोधित पानी का छिड़काव करवा रहा है ताकि नागरिकों को गर्मी से कुछ राहत मिल सके। पानी के छिड़काव से तापमान को कम करने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी ओर प्रदूषण का स्तर भी कम होगा।

नोएडा अग्निकांड: मेघदूतम पार्क में अज्ञात कारणों से लगी भयंकर आग, पहले भी हो चुकी घटना

नोएडा शहर के कोतवाली सेक्टर-49 क्षेत्र के सेक्टर-50 स्थित मेघदूतम पार्क में शनिवार सुबह अचानक से आग लग गई। राहगीरों की माने तो उन्होंने बताया कि पार्क में पड़े पेड़ों के पत्तों में किसी ने बीड़ी या सिगरेट फेंक दी थी जिस कारण से यह आग लग गई। बता दें इससे पहले भी यहां पर आग की घटना हो चुकी है।

नोएडा। कोतवाली सेक्टर-49 क्षेत्र के सेक्टर-50 स्थित मेघदूतम पार्क में शनिवार सुबह अचानक फिर से आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पार्क में पड़े पेड़ों के पत्तों में किसी ने बीड़ी या सिगरेट फेंक दी थी। जिस कारण आग लग गई। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि किसी ने जानकर आग लगाई है। सूचना पर दमकलकर्मी भी पहुंच गए हैं।

जो आग को बढ़ने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले 22 अप्रैल की सुबह भी इसी पार्क में पड़े पत्तों के ढेर में आग लग गई थी। आग लगने के कारण पार्क में घूमने आए लोगों को भरी प्रदूषण का सामना करना पड़ा।

ट्रेन व्हीकल यूनिट सर्वे से जीडीए की निकलेगी लॉटरी, लोगों को मिलेगी जाम से राहत

रेलवे ने ट्रेन व्हीकल यूनिट सर्वे का मंजूरी दे दी है। इससे न सिर्फ जीडीए की लॉटरी निकलेगी बल्कि प्रोजेक्ट तेजी से पूरा होगा और प्रतिदिन हजारों लोगों को लंबा चक्कर लगाकर जाने व जाम की समस्या से निजात मिलेगी। सर्वे के बाद जीडीए की लॉटरी निकलनी तय मानी जा रही है। उपरोक्त आरओबी के लिए पूर्व में साल 2016 में यह सर्वे हुआ था।

गाजियाबाद। मधुबन-बापूधाम रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) पर फर्राटा भरने का पांच साल से इंतजार कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। रेलवे ने ट्रेन व्हीकल यूनिट सर्वे का मंजूरी दे दी है। इससे न सिर्फ जीडीए की लॉटरी निकलेगी, बल्कि प्रोजेक्ट तेजी से पूरा होगा और प्रतिदिन हजारों लोगों को लंबा चक्कर लगाकर जाने व जाम की समस्या से निजात मिलेगी।

जीडीए के मुख्य अभियंता मानवेंद्र सिंह ने बताया कि किसी भी रेलवे फाटक को खत्म करने यानि उसके ऊपर आरओबी बनाने या नीचे अंडरपास बनाने के दौरान रेलवे एक सप्ताह का ट्रेन व्हीकल यूनिट सर्वे कराता है। इसमें यह गणना की जाती है सातों दिन कितनी ट्रेनें ट्रैक के गुजरी व कितने वाहनों ने सड़क मार्ग से रेलवे फाटक आर-पार कर आवागमन किया।

अगर सप्ताह में यह संख्या एक लाख या उससे अधिक होती है तो रेलवे आरओबी या अंडरपास प्रोजेक्ट की कुल लागत में 50 प्रतिशत अंशदान देता है। उपरोक्त आरओबी के लिए पूर्व में साल 2016 में यह सर्वे हुआ था उस वक्त एक सप्ताह में करीब 56 हजार वाहन व ट्रेन गुजरने का आंकड़ा सामने आया था।

रेलवे एक सप्ताह में कराएगा ट्रेन व्हीकल यूनिट सर्वे

जीडीए सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया कि सोमवार को जीडीए के प्रभारी मुख्य अभियंता की रेलवे के मुख्य अभियंता के साथ इसी मुद्दे पर बैठक हुई थी। अब रेलवे एक सप्ताह में ट्रेन व्हीकल यूनिट सर्वे कराएगा।

जीडीए अधिकारियों का कहना है कि ट्रेनों के अलावा फाटक से गुजरने वाले वाहनों की वर्तमान में गणना एक लाख से कहीं अधिक बैठेंगी, क्योंकि मेरठ रोड से उक्त फाटक को पार करते हुए मधुबन-बापूधाम व सदरपुर होते हुए काफी संख्या में लोग गंतव्य तक आते-जाते हैं।

जीडीए ने रेलवे को कर दिया था भुगतान

सर्वे के बाद जीडीए की लॉटरी निकलनी तय मानी जा रही है। रेलवे ट्रैक के ऊपर आरओबी कुल लागत रेलवे ने पूर्व में 24 करोड़ बताई थी जिसका पूरा भुगतान जीडीए द्वारा रेलवे को कर दिया गया था। पिछले दिनों रेलवे ने 10 करोड़ रुपये लागत बढ़ने की बात कहते हुए जीडीए की तरफ से लिखित में आश्वासन मांगा था कि बकाया रकम का भुगतान बाद में कर दिया जाएगा।

इसके बाद अधिकारियों ने मंथन कर फिर से ट्रेन व्हीकल यूनिट सर्वे कराने का निर्णय लिया। अगर रेलवे 50 प्रतिशन अंशदान देता है तो जीडीए व रेलवे के हिस्से में 17-17 करोड़ रुपये का भार जाएगा।

17 के एवज में जीडीए पहले ही 24 करोड़ दे चुका है। ऐसे में जीडीए को रेलवे से सात करोड़ रुपये वापस मिलेंगे। आरओबी निर्माण के लिए जीडीए अपने हिस्से का 85 प्रतिशत काम पूरा कर चुका है। सिर्फ ट्रैक के ऊपर आरओबी का निर्माण बाकी है।

आरओबी से रोजाना 50 हजार से ज्यादा लोगों को होगा फायदा

मधुबन-बापूधाम आरओबी से रोजाना क्षेत्र के 50 हजार से ज्यादा लोगों को जाम व लंबा घूमने की समस्या से राहत मिलेगी। आरओबी के बनने से गाजियाबाद की कई कालोनियां दिल्ली-मेरठ रोड से सीधे जुड़ जाएंगी।

सबसे ज्यादा फायदा मधुबन-बापूधाम आवासीय योजना में रहने वाले लोगों को होगा। गोविंदपुरम, स्वर्णजयंतीपुरम, कर्पूरीपुरम, डासना, मसूरी, सदरपुर गांव, बालाजी एंक्लेव सहित अन्य कालोनियों के लोग सीधे आरओबी से होते हुए दिल्ली-मेरठ रोड पर पहुंच सकेंगे।

प्रोजेक्ट एक नजर में -

- कुल 76 करोड़ रुपये लागत प्रस्तावित है आरओबी की।
- चार लेन के आरओबी की कुल लंबाई 600 मीटर और चौड़ाई 45 मीटर होगी।
- आरओबी का निर्माण सेतु निगम कर रहा

जल-संकट चुनाव जीतने का नहीं, समाधान का माध्यम बने

वास्तव में लगातार बढ़ती गर्मी के कारण जल स्तर में तेजी से गिरावट आ रही है। इसके गंभीर परिणामों के चलते राजस्थान, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में पानी की कमी ने गंभीर रूप धारण कर लिया है।

देश के कई भागों में भीषण गर्मी पड़ रही है, जैसे-जैसे गर्मी प्रचंड होती जा रही है, जल संकट की खबरें भी डराने लगी है। राजस्थान, दिल्ली, कर्नाटक आदि प्रांतों में पानी के लिये त्राहि-त्राहि मची है। मध्यप्रदेश के छतरपुर जलि महर-खुवा गांव में जल-संकट की तस्वीरें भयावह एवं डराने वाली है। इस गांव में लगभग 100 आदिवासी परिवार रहते हैं, जिनके पास अब इतना भी पानी नहीं बचा है कि ये दिन में दो वक्त का खाना बना सकें और अपनी प्यास बुझा सकें। ऐसे हजारों गांव हैं, जहां पानी के अभाव में जीवन संकट में हैं। भारत अपने इतिहास के सबसे गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। लोकसभा चुनाव अन्तिम चरण की ओर अग्रसर है, आज हमारे उम्मीदवार मुफ्त बिजली और पानी देने का वादा करके चुनाव तो जीत जाते हैं लेकिन भारत में जिस तरह पानी का संकट गंभीर हो रहा है, उससे उनकी कथनी और करनी की असमानता ही बार-बार उजागर होती है। जल-संकट चरम पराकाष्ठा पर है, एक दिन ऐसा भी आ सकता है, जब पैसा देकर भी पानी खरीदना मुश्किल हो जाएगा। जल-संकट चुनाव जीतने एवं राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा तो है, लेकिन समाधान का नहीं। जल संकट ने राजनीतिक रंग तो ले लिया है, विभिन्न राजनीतिक दल एक-दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं और पिस रहा आम आदमी। पैसे वालों के लिए पानी इतनी बड़ी समस्या नहीं है लेकिन जिन लोगों के पास पैसों की किल्लत है, वे पानी की किल्लत से भी जूझ रहे हैं क्योंकि टैंकर का पानी महंगा पड़ रहा है।

वास्तव में लगातार बढ़ती गर्मी के कारण जल स्तर में तेजी से गिरावट आ रही है। इसके गंभीर परिणामों के चलते राजस्थान, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में पानी की कमी ने गंभीर रूप धारण कर लिया है। देश का आईटी हब बेंगलुरु गंभीर जल संकट से दो-चार है। जिसका असर न केवल कृषि गतिविधियों पर पड़ रहा है बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी भी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। केंद्रीय जल आयोग के नवीनतम आंकड़े भारत में बढ़ते जल संकट की गंभीरता को ही दर्शाते हैं। आंकड़े देश भर के जलाशयों के स्तर में आई चिंताजनक गिरावट की तस्वीर उकेरते हैं। देश में प्रमुख जलाशयों में उपलब्ध पानी में उनकी भंडारण क्षमता के अनुपात में तीस प्रतिशत की गिरावट आई है। जो हाल के वर्षों की तुलना में बड़ी गिरावट है। जो सूखे जैसी स्थिति की ओर इशारा करती है। महर-खुवा गांव की ही तरह अलवर जिले के कई गांव में लोग किसी एक मौसम में नहीं, बल्कि 12 महीनें भीषण जल संकट का सामना कर रहें है। इन गांवो में पानी का स्त्रोत है ही नहीं। इन इलाकों में पानी की इतनी कमी है कि लोग उसे अपने घरों में टैंकर में छिपाकर और ताला लगाकर सुरक्षित रखने लगे हैं।

भारत के गांवों में रहने वाले करीब 20 करोड़ परिवारों के घरों में नल नहीं है। इन परिवारों की औरतें पैदल चलकर, घंटों लाइन में लगकर पानी इकट्ठा करती हैं। इसी चुनौती से निपटने के लिए मोदी सरकार ने साल 2019 में हर घर में नल से पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन की घोषणा की। सरकार का दावा है कि अब तक 10 करोड़ घरों में नल लग गए हैं। लेकिन अभी हजारों गांवों में जल-संकट एक बड़ी समस्या बनी हुई है। एक नागरिक के रूप में हम आत्ममंथन करें कि बढ़ते जल-संकट के समाधान की दिशा में हमने क्या कदम उठाये। क्या पानी की फिजूल खर्ची को कम करने का कोई संकल्प लिया? गर्मी के आने पर हम हाय-हाय तो करने लगते हैं, लेकिन कभी हमने विचार किया कि हम इस स्थिति को दूर करने के लिये क्या योगदान देते हैं? क्या हम पौधा-रोपण की ईमानदार कोशिश करते हैं? हम जल के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास करते हैं? क्या वर्षा जल सहेजने का प्रयास करते हैं ताकि तापमान कम करने व भूगर्भीय जल के संरक्षण में मदद मिले?

सच कहें तो हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के अनुरूप जैसी जीवन शैली विकसित की थी, वह हमें कुदरत के चरम से बचाती थी। राजस्थान में जल-संकट की संभावनाओं को देखते हुए आम नागरिक खुद के स्तर पर व्यापक प्रयत्न करता है। रेगिस्तान से जुड़े अनेक गांवों एवं शहरों में बने या बनने वाले मकानों में कुआ जरूर होता है, जहां बरसात के पानी को एकत्र किया जाता है, जो संकट के समय काम आता है। इसलिये गाँव के स्तर पर लोगों के द्वारा बरसात के पानी को इकट्ठा करने की शुरुआत करनी चाहिये। उचित रख-रखाव के साथ छोटे या बड़े तालाबों को बनाने के द्वारा बरसात के पानी को बचाया जा सकता है। हम महसूस करें कि बढ़ती जनसंख्या का संसाधनों में बढ़ता दबाव भी तापमान की वृद्धि एवं जल-संकट का कारण है। बड़ी विकास परियोजनाओं व खनन के लिये जिस तरह जंगलों को उजाड़ा गया, उसका खमियाजा हमें और आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। विलासिता के साधनों, वातानुकूलन के मोह, वाटर-पार्कों एवं होटलों में पानी के अपव्यय को रोकने के लिये जन-चेतना जागृत करने की अपेक्षा है।

हमारे पुरखों ने मौसम अनुकूल खानपान, परंपरागत पेय-पदार्थों के सेवन तथा मौसम अनुकूल जीवन शैली के साथ-साथ जल-संरक्षण का ऐसा ज्ञान दिया, जो हमें मौसम के चरम में सुरक्षित रख सकता है। एक व्यक्ति के रूप में हम बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे जल-संकट से खुद व समाज को सुरक्षित कर सकते हैं। सरकार व समाज मिलकर जल-संकट का मुकाबला कर सकते हैं। भारत में जल-संकट की समस्या से निपटने के लिये प्राचीन समय से जो प्रयत्न किये गये है, वे दुनिया के लिये मार्गदर्शक हैं। देश के सात राज्यों के 8220 ग्राम पंचायतों में भूजल प्रबंधनों के लिए अटल भूजल योजना चल रही है।

स्थानीय समुदायों के नेतृत्व में चलने वाला यह दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। साथ ही, नल से जल, नदियों की सफाई, अतिक्रमण हटाने जैसे प्रयास प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उचित ही रेखांकित किया कि सभी राज्यों को मिलकर काम करना होगा तथा जल संरक्षण एवं उपयोग किये गये पानी को फिर से इस्तेमाल में लाने के उपाय करने होंगे। हमारे यहां जल बचाने के मुख्य साधन है नदी, ताल एवं कूप। इन्हें अपनाओं, रक्षा करो, अभय दो, इन्हें मरुस्थल के हवाले न करो। अन्तिम समय यही तुम्हारे जीवन और जीवनी को बचायेंगे।

धरती के क्षेत्रफल का लगभग 70 प्रतिशत भाग जल से भरा हुआ है। परंतु, पीने योग्य जल मात्र तीन प्रतिशत है। इसमें से भी मात्र एक प्रतिशत मीठे जल का ही वास्तव में हम उपयोग कर पाते हैं। 2030 तक देश में पानी की मांग उपलब्ध जल वितरण की दोगुनी हो जाएगी। जिसका मतलब है कि करोड़ों लोगों के लिए पानी का गंभीर संकट पैदा हो जाएगा। स्वतंत्र संस्थाओं द्वारा जुटाए डाटा में दर्शाया गया है कि करीब 70 प्रतिशत प्रदूषित पानी के साथ भारत जल गुणवत्ता सूचकांक में 122 देशों में 120वें पायदान पर है। नीति आयोग ने कहा है, 'अभी 60 करोड़ भारतीय गंभीर से गंभीरतम जल संकट का सामना कर रहे हैं और दो लाख लोग स्वच्छ पानी तक पर्याप्त पहुंच न होने के चलते हर साल अपनी जान गंवा देते हैं।' इन जटिल एवं विकराल स्थितियों एवं डरावने तथ्यों के बावजूद हम पानी का इस्तेमाल करते हुए पानी की बचत के बारे में जरा भी नहीं सोचते, जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश जगहों पर जल संकट की स्थिति पैदा हो चुकी है।

- ललित गर्ग

बीएमडब्ल्यू R20 कॉन्सेप्ट रोडस्टर से उठा पर्दा, 2000 सीसी इंजन के साथ धूम मचाएगी ये बाइक

BMW R20 Concept roadster एक कैफे रेसर या बॉबर की तरह नजर आ रही है। हालांकि कंपनी इसे रोडस्टर कह रही है। मोटरसाइकिल में एक नया डिजाइन किया गया फ्यूल टैंक है जो 1970 के दशक के हॉटर दैन पिंक रंग में फिनिश किया गया है। इसमें क्रोम-मोलिब्डेनम स्टील ट्यूब से बना एक ब्लैक डबल-लूप मेन फ्रेम है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। BMW Motorrad ने एक नई मोटरसाइकिल R20 के कॉन्सेप्ट को किया है। इसे Concorso d'Eleganza Villa d'Este में प्रदर्शित किया जाएगा। R20 कॉन्सेप्ट की खासियत इसकी शिल्पकला और बिग बॉक्सर इंजन है। R20 कॉन्सेप्ट एक कैफे रेसर या बॉबर की तरह नजर आ रही है। हालांकि, कंपनी इसे रोडस्टर कह रही है। अभी तक यह पुष्टि नहीं हुई है कि R20 कॉन्सेप्ट का प्रोडक्शन वर्जन लॉन्च किया जाएगा या नहीं? आइए, इसके बारे में जान लेते हैं।

डिजाइन और डायमेंशन

मोटरसाइकिल में एक नया डिजाइन किया गया फ्यूल टैंक है, जो 1970 के दशक के ₹हॉटर दैन पिंक₹ रंग में फिनिश किया गया है। सिलेंडर हेड कवर, बेल्ट कवर, एयर इनटेक फनल पॉलिश और एनोडाइज्ड एल्यूमीनियम से बने हैं जबकि पैरालेवर स्ट्रट, फुटरेस्ट सिस्टम और ISR ब्रेक कैलीपर्स गनमेटल में फिनिश किए गए हैं।

R20 कॉन्सेप्ट एक सिंगल-सीटर मोटरसाइकिल है, BMW ने रियर LED टेल लैंप को सीट में ही इंटीग्रेट किया है और सीट को क्विल्टेड ब्लैक अल्केन्टारा और फाइन-ग्रेन लेदर में फिनिश किया गया है। एलईडी हेडलैम्प एलईडी डेटाइम रनिंग लैंप के साथ आता है और उनमें 3डी-प्रिंटेड एल्युमीनियम रिंग है।

इसकी चेसिस को पूरी तरह से फिर से डोवलप किया गया है और अब इसमें क्रोम-मोलिब्डेनम स्टील ट्यूब से बना एक ब्लैक डबल-लूप मेन फ्रेम है, जो बैकबोन बनाता है। आगे की तरफ 17 इंच का स्पोक व्हील और पीछे की तरफ 17 इंच का ब्लैक डिस्क व्हील है। पीछे के टायर का माप 200/55 है जबकि आगे की तरफ 120/70 है।

इंजन और परफॉरमेंस

बीएमडब्ल्यू आर20 कॉन्सेप्ट का मुख्य आकर्षण 2000 सीसी की क्षमता वाला एयर-ऑयल-कूल्ड बिग बॉक्सर इंजन है। कॉन्सेप्ट बाइक के लिए, नए सिलेंडर हेड कवर, नया बेल्ट कवर और एक नया ऑयल कूलर विकसित किया गया है, ताकि ऑयल पाइप को आंशिक रूप से छिपाया जा सके। इसमें ट्विन मेगाफोन एग्जॉस्ट पाइप हैं, जो खूबसूरती से तैयार किए गए हैं।

ई-चालान: आपकी गाड़ी पर कितने रुपये का चालान? इन तरीकों से ऑनलाइन करें चेक

नियम का उल्लंघन करने वालों को ई-चालान मिलता है और उन्हें SMS के जरिए सूचना दी जाती है। सबसे पहले https//echallan.parivahan.gov.in/ पर लॉग ऑन करें और Get Challan Details पर क्लिक करें। पूरा प्रोसेस फॉलो करने के बाद पेज पर आपके वाहन से जुड़े सभी ई-चालान की सभी प्रासंगिक जानकारी दिखाई देगी।

नई दिल्ली। मोटर वाहन अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों पर जुर्माना किया जाता है। इन नियमों में समय-समय पर संशोधन भी होते रहते हैं। ओवर-स्पीडिंग, रेड लाइट जंप करना, अनुचित पार्किंग, बिना हेलमेट और सीटबेल्ट ड्राइविंग के साथ वैध लाइसेंस बिना गाड़ी चालाने के मामले सबसे ज्यादा सामने आते हैं। कई राज्यों ने अपराधों का पता लगाने के लिए राजमार्गों को कैमरों और उपकरणों से लैस किया गया है।

E-Challan की ऐसे मिलती है सूचना

नियम का उल्लंघन करने वालों को ई-चालान मिलता है और उन्हें SMS के जरिए सूचना दी जाती है। हालांकि, कई बार लोगों को चालान की सूचना नहीं मिल पाती है। भारी जुर्माने और जेल जाने जैसी स्थिति से बचने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करके आप गाड़ी पर हुए चालान के बारे में जाने सकते हैं।

ऑनलाइन वेबसाइट पर जाएं सबसे पहले

https://echallan.parivahan.gov.in/ पर लॉग ऑन करें और Get Challan Details पर क्लिक करें। सुनिश्चित करें कि आपके वाहन का जरूरी विवरण आपके पास हो। इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर और इंजन नंबर जैसी डिटेल शामिल हैं।

जरूरी सूचना भरें

डेडिकेटेड पेज पर वाहन का पंजीकरण नंबर, चेसिस नंबर या इंजन नंबर दर्ज करें। आवश्यक जानकारी और सत्यापन कोड दर्ज करने के बाद Get Details पर क्लिक करें।

E-challan डिटेल देखें

अगले पेज पर आपके वाहन से जुड़े सभी ई-चालान की सभी प्रासंगिक जानकारी दिखाई देगी। आप चेक कर सकते हैं कि कोई चालान लंबित है या नहीं। यदि कोई चालान लंबित है, तो पोर्टल अपराध के समय और स्थान सहित सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करेगा, साथ ही आपको फोटो प्रूफ भी दिखेगा। इसे देखकर आप ऑनलाइन चालान भी भर सकते हैं।

जावा 42 बॉबर को मिला नया रेड शीन वैरिएंट, जानिए पहले से क्या बदला

Jawa 42 Bobber Red Sheen में एक असिस्ट और स्लिपर क्लच 7-स्टेप प्री-लोड एडजस्टेबल रियर मोनो-शॉक टू-स्टेप एडजस्टेबल सीट USB चार्जिंग पोर्ट डिजिटल कंसोल और फुल LED लाइटिंग भी है। लाल पट्टी के अलावा अपडेटेड Jawa 42 Bobber को रेड शीन को फ्यूल टैंक पर क्रोम फिनिश और ट्यूबलेस टायर के साथ डायमंड-कट एलॉय व्हील्स से पूरित किया गया है।

नई दिल्ली। Jawa Yezdi Motorcycles ने 42 Bobber Red Sheen का नया वेरिएंट लॉन्च किया है, जो बॉबर स्टाइल वाली मोटरसाइकिल में एक नया कलर ऑप्शन लेकर आया है। नई जावा 42 बॉबर रेड शीन, 42 बॉबर का नया टॉप-एंड वेरिएंट है, इसकी कीमत 2.30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) है। नए वेरिएंट में फ्यूल टैंक पर लाल रंग की पट्टी है। मोटरसाइकिल में कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है।

Jawa 42 Bobber Red Sheen में क्या खास?

Jawa 42 Bobber Red Sheen में एक असिस्ट और स्लिपर क्लच, 7-स्टेप प्री-लोड एडजस्टेबल रियर मोनो-शॉक, टू-स्टेप एडजस्टेबल सीट, USB चार्जिंग पोर्ट, डिजिटल कंसोल और फुल LED लाइटिंग भी है।

Jawa का लक्ष्य नए 42 Bobber Red Sheen वेरिएंट के साथ GenZ ग्राहकों की रुचि को आकर्षित करना है। नई कलर स्कीम मूनस्टोन व्हाइट, मिस्टिक कॉपर, जैस्पर रेड डुअल टोन और ब्लैक मिरर सहित मौजूदा रंग विकल्पों के अलावा उपलब्ध होगी। जावा 42 बॉबर के निचले ट्रिम्स में स्पोक व्हील्स दिए गए हैं।

इंजन और परफॉरमेंस

लाल पट्टी के अलावा, नई जावा 42 बॉबर रेड शीन को फ्यूल टैंक पर क्रोम फिनिश और ट्यूबलेस टायर के साथ डायमंड-कट एलॉय व्हील्स से पूरित किया गया है। पावर 334 सीसी लिक्विड-कूल्ड इंजन से आती है, जो 29.4 बीएचपी और 30 एनएम पीक टॉर्क के लिए ट्यून किया गया है। इसे 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है।

लॉन्च के बारे में बात करते हुए, Jawa Yezdi Motorcycles के CEO आशीष सिंह जोशी ने कहा- "Jawa 42 Bobber को अभूतपूर्व सफलता मिली है और हम Red Sheen की शुरुआत के साथ परिवार का विस्तार करने के लिए रोमांचित हैं। यह आकर्षक वेरिएंट बॉबर सेगमेंट में जीवंत ऊर्जा का एक शॉट इंजेक्ट करता है, जो राइडर्स की नई पीढ़ी को पूरा करता है। Jawa Yezdi Motorcycles की उस संस्कृति को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को पूरी तरह से दर्शाता है, जो आत्म-अभिव्यक्ति और सवारी के प्रति प्रेम का जश्न मनाती है।"

डुकाटी स्क्रैम्बलर CR24I और RR24I से लंदन बाइक शेड मोटोशो में उठा पर्दा, जानिए इनमें क्या खास

CR24I कॉन्सेप्ट एक प्योरेस्ट कैफे रेसर स्टाइल की मोटरसाइकिल है। इसकी लाइन 1960 के दशक की ब्रिटिश मोटरसाइकिलों से इंस्पायर्ड है। RR24I के सभी एल्युमीनियम पार्ट्स को हाइलाइट किया गया है और तकनीकी और कार्यात्मक विवरण को उजागर किया गया है। डुकाटी भारत में स्क्रैम्बलर की दूसरी पीढ़ी बेच रही है। यह भारत में आइकॉन थ्रॉटल और नाइटशिफ्ट ट्रिम में उपलब्ध है।

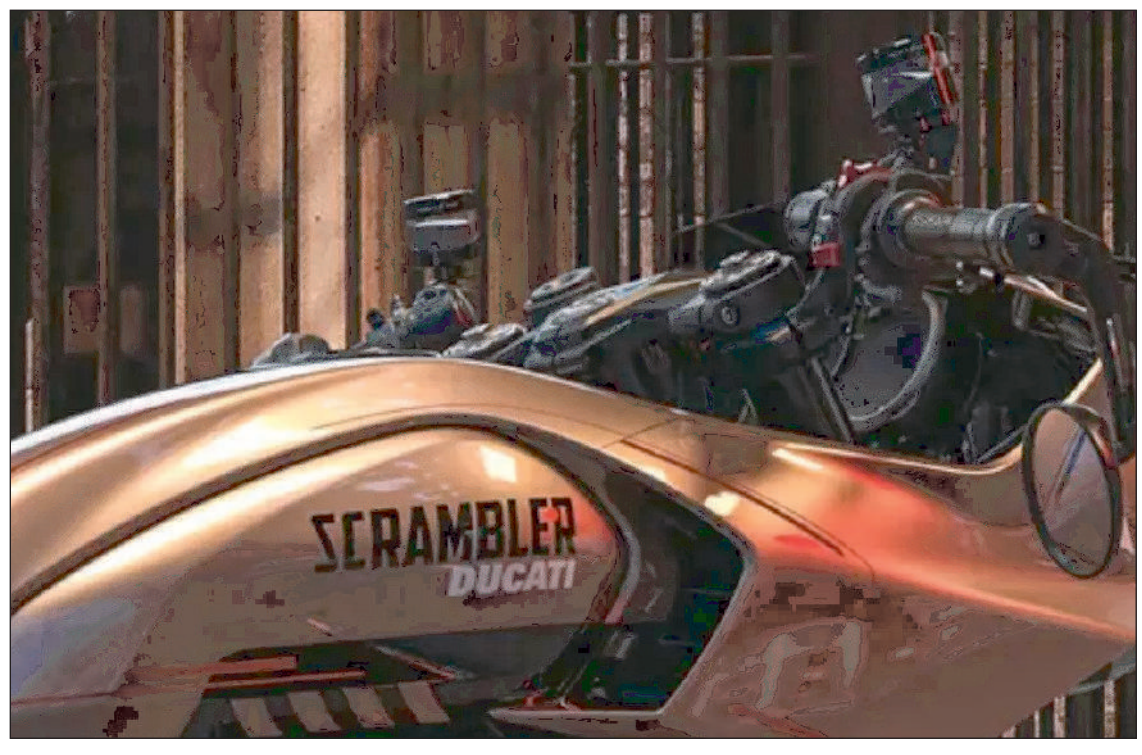

नई दिल्ली। Ducati ने London Bike Shed MotoShow में दो नई कॉन्सेप्ट मोटरसाइकिलें पेश की हैं। दोनों नई कॉन्सेप्ट दूसरी पीढ़ी की स्क्रैम्बलर पर आधारित हैं। कॉन्सेप्ट मोटरसाइकिलों को CR24I और CR24I नाम दिया गया है और इन्हें सेंट्रो स्टाइल डुकाटी द्वारा डिजाइन किया गया है। आइए, इन दोनों के बारे में जान लेते हैं।

Ducati Scrambler CR24I

CR24I कॉन्सेप्ट एक प्योरेस्ट कैफे रेसर स्टाइल की मोटरसाइकिल है। इसकी लाइन 1960 के दशक की ब्रिटिश मोटरसाइकिलों से इंस्पायर्ड है। मोटरसाइकिल में 17-इंच रिम, क्लिप-ऑन हैंडलबार और बार-एंड मिरर का इस्तेमाल किया गया है। फेयरिंग को फ्यूल टैंक पर लगाया गया है और यह डुकाटी पेंटा और 750 SS से प्रेरित है। इसमें एक सिंगल-सीट भी है जो 70 के दशक की स्पोर्ट्स बाइक से प्रेरित है।

Ducati Scrambler RR24I

RR24I के सभी एल्युमीनियम पार्ट्स को हाइलाइट किया गया है और तकनीकी और कार्यात्मक विवरण को उजागर किया गया है। टैंक के कवर हटा दिए गए हैं और उसकी जगह एक फ्रेम लगाया गया है, ताकि जरूरी सामान के लिए टैंक बैग लगाया जा सके।

यात्री के लिए आरक्षित सीट का हिस्सा हटाने योग्य है, ताकि सामान रखने के लिए रैक बनाया जा सके। इसमें एक हाई-पैसेज टर्मिग्नोनी एग्जॉस्ट है, जो फ्लैट-ट्रैकर लुक देता है। टायर आगे की तरफ 18 इंच और पीछे की तरफ 17 इंच के हैं। इन्हें पिरेली स्कॉर्पियन रैली टायर में लपेटा गया है।

Ducati के इंडियन मार्केट में प्रोडक्ट

डुकाटी भारत में स्क्रैम्बलर की दूसरी पीढ़ी बेच रही है। यह भारत में आइकॉन, थ्रॉटल और नाइटशिफ्ट ट्रिम में उपलब्ध है। आइकॉन की कीमत 10.39 लाख रुपये एक्स-शोरूम और फुल थ्रॉटल और नाइटशिफ्ट की कीमत 12 लाख रुपये एक्स-शोरूम है।

इंजन के पुर्जों में भी बदलाव किया गया है। यह अभी भी 803 सीसी, टू-वाल्व, डेस्मोडुओ यूनिट है, जो एयर-ऑयल कूल्ड है। यह पावरट्रेन 8,250 आरपीएम पर 73 बीएचपी और 7,000 आरपीएम पर 65 एनएम उत्पन्न करता है। इसे 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है।

कार के ब्रेक पैड नहीं कर रहे हैं ढंग से काम, तो फॉलो करें ये स्टेप; घर बैठे बदल सकेंगे

परिवहन विशेष न्यूज

सबसे पहले तो आपके नए ब्रेक पैड खरीदने हैं। इसके बाद प्रोसेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ जरूरी टूल इकट्ठा करने हैं। ब्रेक कैलीपर एक धातु का आवरण होता है जो ब्रेक पैड को पकड़कर रखता है। यह आमतौर पहिए के बीचो-बीच होता है। कार के ब्रेक पैड बदलने के बाद कैलीपर को फिर से स्थापित करें।

नई दिल्ली। आपकी कार नई हो या फिर पुरानी, उसे मेंटेन करना बहुत जरूरी है। कार के रखरखाव कार्यों में से ब्रेक पैड बदलना एक महत्वपूर्ण काम है, जिससे हर कार मालिक को परिचित होना चाहिए। यह न केवल आपकी और आपके वाहन की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा बल्कि उन पैसों की भी बचत कराएगा, जो आप मैकेनिक को देने जा रहे हैं। आइए, Brake Pads बदलने के प्रोसेस को स्टेप-बाय-स्टेप जान लेते हैं।

जरूरी टूल इकट्ठा करें

सबसे पहले तो आपके नए ब्रेक पैड खरीदने हैं। इसके बाद प्रोसेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ जरूरी टूल इकट्ठा करने हैं। Brake Pads को घर पर बदलने के लिए आपको जैक, जैक स्टैंड, व्हील चॉक, रिंच, सॉकेट रिंच, स्क्रूड्राइवर, दस्ताने और सेफ्टी ग्लासेस की जरूररत पड़ेगी।

कार को सही जगह खड़ा करें

कार को समतल सतह पर खड़ा करने के बाद, हैंडब्रेक को ऊपर खींचें और कार को जैक से ऊपर उठाएं तथा जैक स्टैण्ड को ठीक से लगाएं।

पहिया निकालें

रिंच का उपयोग करके पहिये में लगे नट को हटाएं। नट को हटाने के बाद, पहिये को सावधानी से बाहर खींचें और इसे गाड़ी से अलग कर लें।

ब्रेक कैलिपर से पैड हटाएं

ब्रेक कैलीपर एक धातु का आवरण होता है, जो ब्रेक पैड को पकड़कर रखता है। यह आमतौर पहिए के बीचो-बीच होता है। ब्रेक कैलीपर पर लगे बोल्ट को ढीला करें और धीरे से उसे हटाएं। पुराने ब्रेक पैड कैलीपर से जुड़े होंगे। उन्हें हटाने के लिए स्क्रूड्राइवर का उपयोग करें।

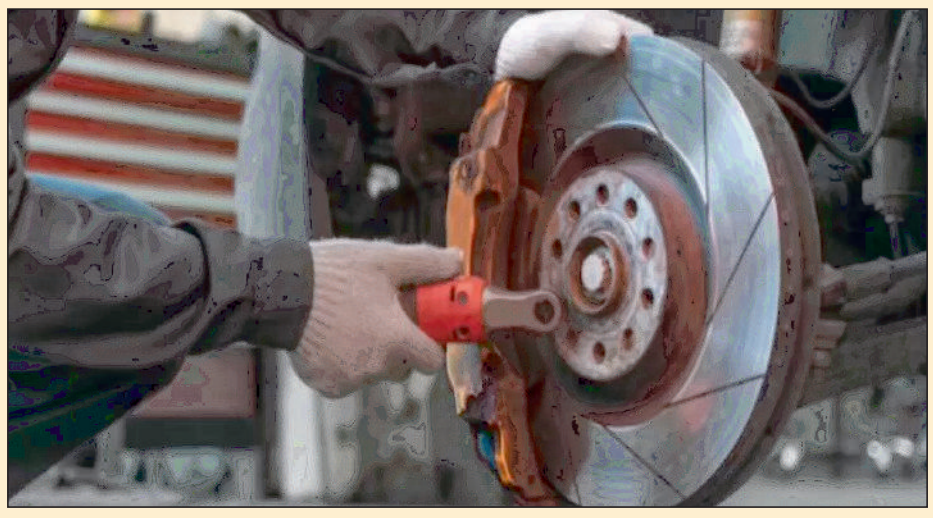

नए ब्रेक पैड लगाएं

सुनिश्चित करें कि नए ब्रेक पैड सही दिशा में हैं। फिर, उन्हें कैलिपर पर सही जगह पर स्लाइड करें और पुराने ब्रेक पैड का तरह लगा दें।

फिर से पहिया लगा दें

ब्रेक पैड बदलने के बाद, कैलीपर को फिर से स्थापित करें। सुनिश्चित करें कि यह ठीक से अलाइन्ड है। बोल्ट लगाएं और उन्हें कस लें। फिर, अगले चरण में पहिया वापस रखें और नट कस लें। एक बार हो जाने के बाद इसके जैक को नीचे करें।

अपनी कार को खाली जगहों पर धीमी गति से ड्राइव के लिए ले जाएं और जांचें कि क्या ब्रेक अलग-अलग गति पर ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। इस तरह आप घर बैठे ब्रेक पैड बदल सकते हैं।

रॉयल एनफील्ड भारतीय बाजार में लॉन्च करेगी ये 5 नई बाइक्स, नई डिटेल्स आई सामने

नई दिल्ली। Royal Enfield घरेलू बाजार में कई नई मोटरसाइकिलें पेश करने की योजना बना रही है। हम आपके लिए ऐसी ही 5 बाइक्स की लिस्ट लेकर आए हैं। आइए, इनके बारे में क्रमवार जान लेते हैं।

Guerrilla 450

Guerrilla 450 के टेस्ट म्यूल्स को जितनी बार देखा गया है, उसे देखते हुए हम aआसानी से पुष्टि कर सकते हैं कि इसका लॉन्च बहुत करीब है। मोटरसाइकिल में नई हिमालयन 450 जैसा ही इंजन और प्लेटफॉर्म होगा, लेकिन इसकी बॉडी स्टाइल में बदलाव होंगे। इसे रोडस्टर के रूप में लॉन्च किया जाएगा। इसकी कीमत भी हिमालयन से कम होने की उम्मीद है।

Classic 350 Bobber

जावा पेराक और 42 बॉबर की बिक्री को देखते हुए यह आरई की बॉबर-स्टाइल मोटरसाइकिल होगी। लेकिन उन मोटरसाइकिलों की तुलना में, आरई क्लासिक 350 बॉबर में व्यापक अपग्रेड नहीं होंगे। इसे स्टब्बी रियर सबफ्रेम, एक फ्लोटिंग राइडर सीट, व्हाइट वाल टायर, एप-हैंगर स्टाइल हैंडलबार और नई शॉटगन 650 की टेललाइट्स और इंडिकेटर्स दिए जाएंगे।

Classic 650 Twin

रॉयल एनफील्ड ने हाल ही में क्लासिक 650 ट्विन नाम का ट्रेडमार्क कराया है और इस मोटरसाइकिल के टेस्ट म्यूल्स को भारत के साथ-साथ यूरोप में भी देखा गया है। क्लासिक 650 ट्विन के बारे में दिलचस्प बात यह है कि इसमें शॉटगन 650 जैसा ही चेसिस होगा, जिसे इंटरसेप्टर से नहीं बल्कि सुपर मेटियोर 650 से बदला गया है।

Bullet 650

कुछ टेस्ट म्यूल्स को देखने के बाद हमें लगता है कि रॉयल एनफील्ड बुलेट को 650 अवतार में लॉन्च करने की योजना बना रही है। बेशक, इसे क्लासिक 650 ट्विन के लॉन्च के बाद ही लॉन्च किया जाएगा और कुछ मामूली बदलावों को छोड़कर डिजाइन काफी हद तक बुलेट के समान ही रहेगा।

संवैधानिक व्यवस्था से ऊपर नहीं ममता सरकार

योगेंद्र योगी

कोर्ट ने सवाल किया कि कोई राज्य सरकार किसी व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट कैसे आ सकती है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सीबीआई जांच का निर्देश देने वाले हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया'

पश्चिम बंगाल की ममता सरकार देश में एकमात्र ऐसी सत्तारूढ़ पार्टी बन गई है जिसका देश के संविधान और न्यायपालिका में भरोसा नहीं रह गया है। भ्रष्टाचार से लेकर मनमर्जी का शासन चलाना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का शगल बन गया है। ममता को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति नजर आती है, इसके लिए बेशक कानून की कितनी ही धज्जियां क्यों न उड़ानी पड़े। ममता बनर्जी का एकमात्र लक्ष्य मुसलमानों के वोट बैंक को बरकरार रखना रह गया है। मुद्दा चाहे रोहिंग्या मुसलामानों के अवैध प्रवेश का हो या फिर बांग्लादेशियों का, इसके लिए ममता ने देश की एकता-अखंडता और सुरक्षा से जुड़े इन मुद्दों पर भी केंद्र की भाजपा सरकार की खिलाफत की है। कानून से खिलवाड़ जितना पश्चिम बंगाल में हुआ है, उतना शायद ही देश के किसी दूसरे राज्य में हुआ हो। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के हाईकमान ने भी कभी ऐसे आरोप केंद्र की भाजपा सरकार पर नहीं लगाए, जैसे कि ममता बनर्जी लगाती रही हैं। ममता ने भ्रष्टाचार, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग, राजनीतिक आधार पर बंदरबाट जैसे मुद्दों पर अदालतों से जितनी फटकार खाई है, उतनी देश के किसी राजनीतिक दल की सरकार ने नहीं खाई। इतना सब कुछ होने के बावजूद ममता बनर्जी अपनी आदतों से बाज नहीं आई हैं। नया मामला पश्चिम बंगाल में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण को अदालत द्वारा रद्द करने का है। इस आदेश को सदाशयता से मान कर अपील करने की दलील देने के बजाय मुख्यमंत्री ममता ने ही फैसला देने वाले हाईकोर्ट के न्यायाधीश पर भाजपा समर्थक होने का आरोप लगा दिया।

ऐसा करके ममता ने बगैर किसी भय के सरेआम अदालत की अवमानना कर दी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वह इस आदेश को स्वीकार नहीं करेंगी, जो तपशिली समुदाय को दिए गए अधिकार छीन लेगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस प्रशासन के तहत 2011 से बंगाल में जारी अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी प्रमाणपत्रों को अवैध बताते हुए रद्द कर दिया। अदालत ने कहा, हालांकि, इससे वर्तमान में शैक्षणिक संस्थानों में नौकरी या सीटें रखने वाले या जाति प्रमाणपत्र के साथ आवेदन दाखिल करने वाले लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण की पूरी कहानी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में गठित सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर आधारित है। उस रिपोर्ट में देश में मुस्लिम समुदाय की स्थिति के बारे में विस्तृत बातें की गई थीं। रिपोर्ट में कहा गया था कि पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों में केवल 3.5 फीसदी ही मुस्लिम थे। इसी को आधार बनाकर 2010 में पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार ने 53 जातियों को ओबीसी की श्रेणी में डाल दिया और ओबीसी आरक्षण सात फीसदी से बढ़ाकर 17 फीसदी कर दिया। इस तरह उस वक्त करीब 87.1 फीसदी मुस्लिम आबादी आरक्षण के दायरे में आ गई। लेकिन, 2011 में वाम मोर्चा की सरकार सत्ता से बाहर हो गई और उसका यह फैसला कानून नहीं बन सका। फिर राज्य में तृणमूल कांग्रेस की सरकार आई और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनीं। ममता की सरकार ने इस सूची को बढ़ाकर 77 कर दिया। 35 नई जातियों को इस सूची में जोड़ा गया, जिनमें से 33 मुस्लिम समुदाय की जातियां थीं। साथ ही तृणमूल सरकार ने भी राज्य में ओबीसी आरक्षण सात फीसदी से बढ़ाकर 17 फीसदी कर दिया। ममता सरकार के इस कानून की वजह से राज्य की 92 फीसदी मुस्लिम आबादी को आरक्षण का लाभ मिलने लगा। हाइकोर्ट ने ओबीसी के मामले में सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया।

इसके बाद तो मानो ममता का पारा उछल गया। ममता ने अदालत पर मनमाने आरोप लगा दिए। उच्च न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीशों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक न्यायाधीश कह रहा है कि मैं आरएसएस का आदमी हूं, दूसरा भाजपा में शामिल हो जाता है। आप इस तरह से न्यायाधीश कैसे बन सकते हैं और अदालतों की अध्यक्षता कैसे कर सकते हैं? पार्टी के वरिष्ठ नेता और सुश्री बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी आरोप लगाया कि अदालत का फैसला तपशिली समुदाय के लिए आरक्षण रद्द करने के भाजपा के प्रयासों का हिस्सा है। ममता के आरोपों के जवाब में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सुश्री बनर्जी की टिप्पणियों को खारिज कर दिया। शाह ने कहा कि ममता जी ने कहा कि हम उच्च न्यायालय के फैसले को स्वीकार नहीं करते हैं। शाह ने कहा कि बंगाल के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या ऐसा कोई मुख्यमंत्री हो सकता है जो अदालत के आदेश को मानने से इनकार कर दे? उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने बिना किसी सर्वेक्षण के 118 मुस्लिम जातियों को ओबीसी आरक्षण दे दिया। कोई अदालत में चला गया। ममता बनर्जी अपने वोट बैंक के लिए पिछड़े वर्गों के आरक्षण को लूटना चाहती हैं और मुस्लिम जातियों को आरक्षण देना चाहती हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि ये दोनों ही जो फैसले हैं, वो बताते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार गैर-संवैधानिक तरीके से तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ा रही थी। ममता बनर्जी ने वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति करने में कसर बाकी नहीं रखी। मुद्दा चाहे रामनवमी पर हिंसा का हो या संदेशखाली में हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचारों का। राज्य में शीर्ष संवैधानिक पद पर रहते हुए भी ममता बनर्जी ने मुसलमानों के वोट बैंक को रिझाने के लिए उल्टे भाजपा और दूसरे विपक्षी दलों पर ही निशाने साधे हैं।

इसके अलावा ममता बनर्जी के मौजूदा और पूर्व कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार का ताडंव जम कर हुआ। शारदा घोटाला और नारद स्टिंग खुलासे, कोयला और मवेशी तस्करी, राशन घोटाले और सरकारी परियोजनाओं के लिए फंड से लिए गए कट मनी के आरोपों के बावजूद ममता सरकार में कोई सुधार नहीं दिखा। इससे जाहिर है कि ममता बनर्जी मनमानी करने पर आमदा हैं। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला, कोयला तस्करी मामला, नगरपालिका नियुक्ति घोटाला व राशन वितरण घोटाले में तृणमूल कांग्रेस के एक दर्जन से अधिक नेता व मंत्री सलाखों के पीछे हैं।

इनमें पूर्व मंत्री व विधायक पार्थ चटर्जी, विधायक अनुब्रत मंडल, विधायक मानिक भट्टाचार्य, विधायक जिबनकृष्ण साहा प्रमुख हैं। इस कड़ी में वन मंत्री व पूर्व खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक का नाम जुड़ गया है। करोड़ों रुपए के शारदा चिट फंड घोटाले में तृणमूल के तत्कालीन राज्यसभा सदस्य संजय बोस और तृणमूल के विधायक व तत्कालीन परिवहन मंत्री मदन मित्रा को गिरफ्तार किया गया था। मित्रा और बोस दोनों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। बंगाल पुलिस ने शारदा चिट फंड घोटाले में टीएमसी के प्रवक्ता और पार्टी के पूर्व राज्यसभा सदस्य कुणाल घोष को गिरफ्तार किया था। ममता सरकार की सर्वाधिक किरकिरी संदेशखाली की शर्मनाक वारदात में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने संदेशखाली मामले की सीबीआई जांच का विरोध करने पर पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने सवाल किया कि कोई राज्य सरकार किसी व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट कैसे आ सकती है।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सीबीआई जांच का निर्देश देने वाले हाई कोर्ट के आदेश पर कोई रोक लगाने से इनकार कर दिया और पूछा था कि राज्य सरकार किसी व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय से कैसे संपर्क कर सकती है? जहां तक वोटों की राजनीति और बहुमत पाने से काले कारनामों के धुल जाने का सवाल है तो लालू यादव बहुमत के बावजूद जेल गए थे। लोकतंत्र में कानून से खिलवाड़ करने के लिए बहुमत को आधार नहीं माना जा सकता। ममता बनर्जी को इससे अवश्य ही सबक लेना चाहिए।

संपादक की कलम से

आरक्षण का ही देश नहीं

यह देश किसी एक जाति, संप्रदाय, नस्ल, वर्ग, भाषा और जमात का नहीं है। यह देश हिंदू-मुसलमान या जैन-बौद्ध अथवा सिख-जट या पारसी-ईसाई आदि का भी नहीं है। यह देश दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों का भी है तथा अल्पसंख्यक सवर्ण गरीबों का भी है। यह देश समस्त भारतीयों का है, लिहाजा सभी के दुख-सुख और हित में सोचना और नीतियां बनाना अनिवार्य है। दुर्भाग्य और विडंबना है कि इस बार के आम चुनाव में इस विविधता और व्यापकता पर कोई बहस नहीं की गई। सिर्फ मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा सबसे अधिक गूंजता रहा है। विपक्ष के खेमे का लगभग समवेत स्वर रहा है कि मुसलमानों को आरक्षण जरूर देंगे। लालू यादव तो 100 फीसदी आरक्षण मुसलमानों को ही देने के पैरोकार हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उच्च न्यायालय के फैसले के बाद सार्वजनिक ऐलान किया है कि मुस्लिम आरक्षण जारी रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी लगातार पलटवार करते रहे हैं कि वह मुस्लिम आरक्षण लागू नहीं होने देंगे। जब तक वह जिंदा हैं, तब तक दलितों, आदिवासियों और ओबीसी का आरक्षण छिनने नहीं देंगे। आरक्षण किसी का संवैधानिक मौलिक अधिकार नहीं है। हमारे संवैधानिक पुरखों ने एक व्यवस्था 10 साल के लिए तय की थी, ताकि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विषमताएं समाप्त की जा सकें, लेकिन आजादी के 77 साल बाद भी वह 'संवैधानिक कृपा' बरकरार है, विषमताएं भी मौजूद हैं, क्योंकि आरक्षण आज भी लागू है। बल्कि आरक्षण आज राजनीतिक हथियार बन चुका है। संविधान पीठ भी फैसला दे चुकी है कि धर्म पर आधारित आरक्षण 'संवैधानिक' नहीं है।

कुछ राज्य सरकारों ने मुसलमानों को धार्मिक कोटा देने की जुर्रत की थी, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने उन्हें खारिज कर दिया। सिर्फ बिहार और बंगाल ही नहीं, मध्यप्रदेश, गुजरात, उप्र, केरल, आंध्रप्रदेश, ओडिशा आदि राज्यों में भी कई-कई जातियों की आड़ में मुसलमानों को आरक्षण देने की व्यवस्था है। अदालत की आंख में धूल झोंकी गई है। कई राज्यों में तो भाजपा की सरकारें है। कुछ भी संवैधानिक नहीं है, फिर भी आरक्षण का चुग्गा फेंक कर मुस्लिम तुष्टिकरण और बंधक वोट बैंक की राजनीति खेली जा रही है। मुसलमानों की आड़ में बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या सरीखी देश-विरोधी गतिविधियां भी जारी हैं। यह कड़ा आदेश मुख्यमंत्रियों को भी दिया जाना चाहिए कि ऐसे रंगे सियार वोट बैंक असंवैधानिक हैं, लिहाजा देश में एनआरसी भी अनिवार्य की जानी चाहिए। अब तो कुछ दिनों के बाद नई सरकार भारत में बनेगी, लिहाजा वोट बैंक की चिंताएं कम होंगी, लिहाजा भारत सरकार ऐसा अभियान चलाए, ताकि अवैध घुसपैठियों को देश से बाहर किया जा सके। हम पूरा दोष घुसपैठियों को या वोट बैंक के तुष्टिकरण को ही नहीं दे सकते, क्योंकि देश में ही कांग्रेस पूरी तरह 'मुस्लिमवादी' रही है। मुस्लिमवादियों के अपने कुतर्क हैं। कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार ने ही 2004 में जस्टिस रंगनाथ मिश्र आयोग गठित किया था। उसने 2007 में मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण देने की सिफारिश की थी। जस्टिस रंगनाथ मिश्र देश के प्रधान न्यायाधीश रह चुके थे। मुसलमानों के लिए ही सच्चर कमेटी का गठन किया गया। यूपीए सरकार के तहत अलग से 'अल्पसंख्यक मंत्रालय' भी बनाया गया, जिसका फोकस मुसलमानों पर ही रहा है।

उस दौर में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का विवादास्पद बयान भी सामने आया कि देश के संसाधनों पर पहला दावा और अधिकार खासकर अल्पसंख्यक मुसलमानों का है। 2024 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी का 2012 का एक वीडियो बेनकाब किया है, जिसमें राहुल मुस्लिम आरक्षण का दावा ठोंकते देखे और सुने जा सकते हैं। सवाल है कि इन सरकारों को महज मुसलमानों की ही चिंता क्यों सताती रही है? उनके सरोकार और कार्यक्रम भी मुस्लिम सम्मत क्यों रहे हैं? क्या भारत सिर्फ उन्हीं का देश है? वे करीब 15 फीसदी आबादी हैं। शेष 85 फीसदी आबादी क्या हाथ मलती रहे? यह संवैधानिक न्याय नहीं है। मदद उनकी की जानी चाहिए, जो विपन्न, वंचित और निरक्षर हैं, चाहे उनकी जाति और समुदाय कुछ भी हो।

चर्चा

हिमाचल के सियासी गुनाह-1

हम जिस तकदीर को सियासत को सौंप देते हैं, वही हमारे फैसलों के गुनाह में शरीक होती है। ऐसा नहीं कि जो नेता अपराजेय रहे, वही कद्दावर हो गए, कई बार हार कर भी मंजिलें कबूल करती हैं। हिमाचल अपने अस्तित्व से आज तक और वर्तमान से भविष्य तक जिस नेतृत्व को अंगीकार करता रहा या आइंदा देख रहा है, क्या वही सत्य है। कई झूठ भी जीत जाते हैं हमारी रजामंदी से, हमें तो अपनी राख होना भी इज्जत देता रहा। ऐसा भी नहीं कि प्रदेश में सियासत ने ही हमेशा धोखा दिया, बल्कि कई बार समाज की हसरतों ने कत्ल किए हैं। मंडी के ठाकुर कर्म सिंह के नाम से इस राज्य की तासीर बदल जाती, गर उस दौर की सूझबूझ में हुक्मरान चुनने की बगावत होती। यह ठीक है कि वाईएस परमार हिमाचल के निर्माता के रूप में ऐसी शोहरत के पात्र हैं जो सदियों बाद भी इस राज्य की आत्मा में निवास करेगी, लेकिन यह भी सत्य है कि हिमाचल के बाद के विस्तार में उनकी भूमिका का कोई सूर्य नहीं। जिस हिमाचल को आज हम देखते हैं या जिस राजधानी शिमला में प्रदेश की बहुआयामी तस्वीर देखते हैं, वह हिस्सा कभी पंजाब से निकल कर हिमाचल में पहाड़ी दिल खोजता रहा। आज भी हिमाचल में तफतीश यही है कि इसका पहाड़ी दिल है कहां। क्या पहाड़ी नेताओं की बदौलत पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल में मिले या उन्होंने पंजाबी सूबा बनाने के लिए हिमाचल का सियासी कोष बढ़ा दिया। हिमाचल पहले जिन बिस्वों व बीघों में पैमाइश करता था, वह अगर कनाल या हेक्टेयर में खुद को मापने लगा, तो उस भौगोलिक दौलत में सियासत ने खुद को कमजोर, खुदगर्ज और स्कीर्णता के स्वार्थों में पिरो लिया। युद्ध तो तब वाई एस परमार को भी लडऩा पड़ा, इसलिए जिलों की कांट छांट में इस सरहद पर आकर कुछ गिल्लियां उड़ाई गईं। तब राजनीति ने शिमला के मुकाम पर कांगड़ा की दूरी ही नहीं बढ़ाई, बल्कि मैदान के बालू को भी अलग-अलग तश्तरियों में बांट दिया। यही बालू अब हमीरपुर के नेतृत्व में सरकारों के बदन में कांगड़ा को डराता है।

कभी धूमल सरकार ने डराए, तो अभी सुक्खू सरकार ने हाशिए की ओर सरका कर, लेकिन सत्य यह भी है कि वर्तमान सरकार के खिलाफ हुई राज्यसभा की वोटिंग का उफान उन्हीं क्षेत्रों में उठा, जिन्होंने कभी पंजाब से छिटक कर हिमाचल की ओर कदम बढ़ाए थे। अगर गिनती कर सकते हैं तो कर लें कि लाहुल-स्पीति, हमीरपुर व ऊना से अपनी ही सरकार के विरोध में पुराना कांगड़ा क्यों आजाद हुआ। हम यह तो नहीं कहते कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष को जिता कर बागी विधायकों को साधुवाद दिया जाए, लेकिन जनता की अदालत में उसी का जनादेश आज कसूरवार जरूर हुआ। ऐसा क्यों है कि पंजाब से हिमाचल में 'आन मिलो' कहते हुए अधिकांश नेता शहीद हो रहे हैं। क्यों मेजर विजय सिंह मनकोटिया, राजन सुशांत, किशन कपूर, विपिन सिंह परमार, रमेश धवाला व वीरेंद्र कंवर सरीखे नेताओं को परिदृश्य से हटाने से राजनीति ने विक्ट्री का चिन्ह बनाया। निचले हिमाचल या यूं कहें कि पंजाब से हिमाचल में जुड़े पर्वतीय क्षेत्रों से जब भी कोई मुख्यमंत्री बना, कुछ नेताओं के जनाजे उठाने का घटनाक्रम भी चला। दो बार शांता कुमार की आधी सत्ता का सफर सियासी कब्रिस्तान के इर्द-गिर्द क्यों चक्कर काटता रहा।

रमेश पठानिया

पौंग सेंक्चुरी में माफिया का अतिक्रमण

ऐसा प्रतीत होता है कि बीबीएमबी का भी गुज्जर माफिया, अवैध खेती और अन्य गतिविधियों के प्रति मूक बने रहने के पीछे स्वार्थ है'

साल 1971 में पौंग बांध के निर्माण के बाद नहरों का जाल बिछने से राजस्थान की रेतीली ज़मीन तो सोना उगलने लगी लेकिन कांगड़ा जिले के 339 डूबे गांवों के हजारों परिवारों के दिलों में कभी न भर पाने वाले ज़ख्म छोड़ गयी। गत 50 साल से अधिक समय से पौंग बांध विस्थापन ने बेशुमार विवादों, जनसमस्याओं को जन्म दिया है। सरकार, प्रशासन, $खासकर राजनेताओं की अनदेखी, संवेदनहीनता के कारण पौंग डैम वेटलैण्ड तथा वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी की मूल्यवान धरोहर को नष्ट करने के मन्सूबों पर कोई अंकुश नहीं दिखाई दे रहा। पौंग डैम महज़ विस्थापन की समस्या नहीं है। इसके बेशुमार शेड्स हैं। फिलहाल इस लेख का मकसद वैटलैंड एरिया में गुज्जरों के अस्थायी डेरों से पर्यावरण और वन्य जीव-जन्तुओं के बर्बाद होने की ज्वलन्त समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करना है। देश भर में कुल 662 वन्य जीव अभयारण्य हैं जिनमें से पौंग डैम का 207.59 कि. मी. दूर तक फैला क्षेत्र भी शामिल है। साल 1972 में हिमाचल सरकार ने वाइल्ड लाइफ प्रोटैक्शन एक्ट पास किया था जिसके सेक्शन 27 के मुताबिक सेंक्चुरी एरिया में किसी भी प्रकार की गतिविधियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध है ताकि वन्य जीव-जन्तु, पक्षी, मधुमखियां, तितलियां व सभी प्रकार के वन्यजीव सुरक्षित रह सकें। लेकिन गत 50 साल से जम्मू-कश्मीर, पंजाब के अनेक क्षेत्रों से बड़ी तादाद में गुज्जर अपनी भैंसों, गायों व अन्य पालतू पशुओं के साथ बेरोकटोक पौंग डैम में पानी के किनारों की ज़मीन को अपना अस्थायी आशियाना बना लेते हैं।

पौंग डैम में बीबीएमबी की हजारों एकड़ भूमि में राजनेताओं की कथित द$खलअंदाजी व माफिया दबंगई के बाद बीजी गयी गेहूं की फसल कटने के बाद अप्रैल से जुलाई-अगस्त तक गुज्जर समुदाय के लोग अपनी हजारों भैंसों के साथ हरी भरी उपजाऊ ज़मीन पर डेरा जमा लेते हैं। कोई 60 हजार से ज्यादा भैंसों के गोबर, गून्तर से और सडक़ों तक में विचरने से स्वच्छता अभियान को ठेस लग रही है। भैंसों के साथ आए गुज्जरों के परिवार खुले में शौच करते हैं और मल-मूत्र जनित बीमारियों पैदा करते हैं। भैंसों के चरने से उनके खुरों से ज़मीन नरम हो जाती है और मानसून के आते ही यह गन्दगी व रेत पौंग डैम के पानी में जमा हो रही है। इससे डैम में भारी मात्रा में गाद जमा हो रही है। पर्यावरणविदों का आरोप है कि गुज्जर कट्टियों को तो संभाल कर रखते हैं, लेकिन कट्टुओं को पैदा होते ही मार देते हैं और उन्हें डैम के पानी में बहा देते हैं। ऐसी क्रूरता के उदाहरण भी कम नहीं हैं जब वे कट्टुओं का गला काट कर उनका सिर भैंसों के आगे रख देते हैं ताकि वो दूध के लिए न बिफरें। पालतू पशुओं के साथ यह क्रूरता की इन्तहा है जिस पर गुज्जरों के $खिलाफ मुकद्दमें दर्ज होने चाहिएं। मरे हुए पशुओं से पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है, इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। बीबीएमबी की जमीन पर जिसे वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी और अंतरराष्ट्रीय स्तर का वैटलैण्ड और रैमसर साइट घोषित किए गए हैं, उस पर गुज्जर समुदाय का माफिया बेखौफ अवैध गतिविधियों में संलिप्त है। हैरत यह है कि पुलिस, प्रशासन, सरकार, राजनेता सब चुप्पी साधे हुए हैं। मूल रूप से गुज्जरों की 'तानाशाही' के लिए हिमाचल सरकार का वन विभाग का वाइल्ड लाइफ विंग जिम्मेदार है। लेकिन वह क्यों आंखें मूंदे बैठा है, इसकी वजह पौंग डैम एरिया में सक्रिय पर्यावरणविद बताते हैं, ''राजनेता, पुलिस, बीबीएमबी और वन विभाग के अधिकारियों का पौंग बांध में सक्रिय माफिया

के साथ कथित रूप से गठजोड़ और अलिखित संधि है। प्रवासी परिन्दों को देखने, नौका विहार करने और वन सम्पदा का अवलोकन करने के लिए देश-विदेश से असंख्य सैलानी आते हैं।

लेकिन 50 साल में माफिया ने सेंक्चुरी और वैटलैण्ड में अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देकर मुनाफे के लिए इसका लगातार दोहन किया है और पर्यावरण को बुरी तरह रौंद डाला है। हर साल सर्दियों में साइबेरिया से आने वाले करीब डेढ़ लाख प्रवासी परिन्दों का शिकार जारी है। वन विभाग द्वारा शिकारियों को पकडने और उन्हें सज़ा दिलाने के प्रयास कहीं नहीं दिखाई देते। इस मामले में स्थानीय ग्राम पंचायतों के प्रधान व वार्ड मेम्बर भी अपने दायित्व के निर्वहन के प्रति खामोश हैं। बताते हैं कि गुज्जर समुदाय के लोग छह महीने तक अपने डेरे जमाए रखने के लिए अफसरों को लाखों का चढ़ावा चढ़ाते हैं और यहां मजे से डटे रहते हैं। पौंग बांध क्षेत्र में विगत एक दशक से सक्रिय एक अग्रणी पर्यावरणविद मिलखी राम शर्मा ने हिमाचल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। 7 अक्तूबर 2023 को याचिका संख्या 41/2023 का फैसला हुआ था। न्यायालय ने गुज्जरों की भैंसों से पैदा होने वाली पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं का कड़ा संज्ञान लेते हुए हिमाचल सरकार को निर्देश दिए थे, 'हम विश्वास व आशा करते हैं कि पौंग डैम वेटलैण्ड क्षेत्र व वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी को बर्बाद करने के प्रयासों पर तुरन्त प्रतिबन्ध लगेगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव, (वन), पीसीसीएफ (वाइल्ड लाइफ), सीसीएफ (नार्थ), धर्मशाला व हमीरपुर के डीएफओ (वाइल्ड लाइफ), एसपी व डीसी कांगड़ा इस विषय में कोर्ट के आदेशों को लागू करें। दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें।' लेकिन धरातल पर सरकार के उक्त सभी अधिकारियों की कार्रवाई शून्य है। मिलखी राम शर्मा व उनकी एनजीओ के अन्य सदस्य शीघ्र ही हिमाचल सरकार के अधिकारियों के विरुद्ध कोर्ट की अवमानना का केस दायर करने का मन बनाए हुए हैं।

इस मामले में भाखड़ा ब्यास मैनेजमेन्ट बोर्ड की चुप्पी भी अ$खरती है। अपनी ड्यूटी के प्रति अवहेलना की यह पराकाष्ठा है। आखिर क्यों वे अपनी ज़मीन पर अवैध गतिविधियों के प्रति कबूतर की तरह आंखें मूदे हुए हैं। डैम में लगातार सिलटिंग की समस्या के प्रति चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि बीबीएमबी की भी गुज्जर माफिया, अपनी ज़मीन पर अवैध खेती और अन्य गतिविधियों के प्रति मूक बने रहने के पीछे कोई निहित मन्शा है। साल 2008 के बाद पौंग डैम के कुठेड़ा टापू और पौंग डैम से विस्थापित परिवारों के प्रत्येक गांव में चुनाव बूथ स्थापित हो रहे हैं। लेकिन वे क्यों अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं शायद वे खुद नहीं जानते। इस बार यहां के हजारों वोटरों ने भी मन बनाया है कि वे राजनेताओं को सबक सिखाने के लिए संभवतः नोटा का प्रयोग करेंगे?

अटैची गए कहां'

भीषण गर्मी पड़ रही है। सूर्य भी प्रचंड हो रहा है और मुखिया का भाषण भी आग उगल रहा है। यानी भाषण और गर्मी की दोहरी मार पड़ रही है। भाषण अटैची से शुरू होता है और अटैची पर खत्म हो जाता है। पब्लिक प्रचंड गर्मी से भी हलकान है और नेताजी के 'राग अटैची' की रहस्यमयी गुत्थी सुलझाने में भी नाकाम है। पब्लिक जगह-जगह पूछ रही है कि अटैची दिए गए थे तो अटैची गए कहां? जब अटैची दिए जा रहे थे तो सरकार कहां सोई थी और सरकार की सीआईडी कहां सोई थी? जब सरकार भी सोई थी और खुफिया एजेंसियां भी सोई थी, तो फिर जाग कौन रहा था? सरकार के बारे में तो माना जा सकता है कि सत्ता के नशे में चूर होकर सोई हुई थी। लेकिन गुप्तचर एजेंसियों की आंखों पर पट्टी किसने बांध रखी थी? किसी ने किसी को अटैची देते नहीं देखा और किसी ने किसी को अटैची लेते नहीं देखा। एक साथ कितने अटैची खरीदे गए थे, किस शहर से खरीदे गए थे, किस दुकान से खरीदे गए थे, इसका कोई बिल भी सरकार पेश नहीं कर पा रही। यह तो सरकार को जीएसटी में भी हुआ सीधा-सीधा नुकसान है। जीएसटी का भुगतान नहीं हुआ तो सरकारी खजाने को चपत लग गई। अब ऐसी कौनसी ताकत थी जो सरकारी खजाने को भी चपत लगा गई और सरकार के मुलायम मुलायम गाल पर भी चपत लगा गई। गाल अभी तक लाल हैं। यह शर्म से भी लाल हो सकते हैं और गुस्से से भी लाल हो सकते हैं क्योंकि गाल लाल दो तरह से होते हैं। अगर गुस्से से लाल हैं तो सरकार को तुरंत अपना गुस्सा बाहर निकाल देना चाहिए।

सरकार अगर अपने भीतर गुस्सा रखती है तो सरकार को कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। रक्तचाप बढ़ जाता है। लेकिन अगर गाल शर्म से लाल हैं तो सरकार को आत्ममंथन करना चाहिए कि शर्म के इन पलों की उत्पत्ति कैसे हुई? अटैची में न तो गुस्सा छिप सकता है और न ही शर्म छिपाई जा सकती है। अटैची इस काम के लिए नहीं बने हैं। हम आम तौर पर अटैची में अपना जरूरत का सामान डालकर सफर करते हैं। लेकिन अटैची राजनीतिक मुद्दा और चुनावी मुद्दा क्यों बन गए, इस बारे बड़ा असमंजस का माहौल है। पब्लिक कंफ्यूज है कि बड़े नेताजी अपनी उपलब्धियों के नाम पर वोट नहीं मांग रहे सिर्फ अटैचियों की बात कर रहे हैं। क्या पब्लिक से जुड़े मुद्दे चुनाव में गौण हो जाते हैं या फिर अपनी नाकामियां छिपाने के लिए सरकार जनता का ध्यान बांटना शुरू कर देती है? पब्लिक कह रही है कि हमें महंगाई से निजात दो। युवा कह रहे हैं कि हमें नौकरी दो। कर्मचारी और पेंशनर कह रहे हैं कि हमारे एरियर का भुगतान करो।

किसान और बागवान कह रहे हैं कि हमें उचित समर्थन मूल्य दो। लेकिन नेताजी इन सारे सवालों से अपना पिंड छुड़ाते हुए कह रहे हैं कि अटैची देने वाले और अटैची लेने वाले एक दिन सलाखों के पीछे जाएंगे। पब्लिक परेशान होकर पूछ रही है कि हमारे मुद्दों पर भी जो अटैची भारी पड़ गए, वे अटैची आखिर हैं कहां? नेताजी कह रहे हैं कि अटैची तो पता नहीं लेकिन सबूत उनके पास हैं। पब्लिक को अटैची लेने और देने का सबूत नहीं चाहिए, पब्लिक को तो बस यही सबूत चाहिए कि सरकार ने कितनी नौकरियां दी। कितने वादे पूरे किए। खाद्य पदार्थों की कीमतों को कितना कम किया। नेताजी पब्लिक की इस मांग से सहमत नहीं हैं। पब्लिक की समस्याओं और सवालों की बजाय अटैची को बड़ा मुद्दा मानते हैं। इसलिए घूम फिर कर सवाल वहीं खड़ा हो रहा है कि अटैची आखिर गए कहां? जमीन निगल गई या आसमान खा गया?

-गुरमीत बेदी

पूरी दुनिया में फेल, भारत में कैसे सफल हुए 10 मिनट में सामान पहुंचाने वाले ब्लिंकिट-जेप्टो जैसे प्लेटफॉर्म?

भारत में क्विक कॉमर्स का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। खासकर नौजवान उपभोक्ताओं के बीच इनकी लोकप्रियता एक अलग ही लेवल पर पहुंच गई है। वे अपनी जरूरत का हर छोटा-बड़ा सामान यहां से मंगा रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि क्विक कॉमर्स दुनिया के बाकी देशों में ज्यादा सफल नहीं रहा। लेकिन भारत में इसकी कामयाबी मिसाल बन गई है।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। आपका ऑफिस जाने से पहले ब्रेड के साथ चाय पीने का मन है। किचन पहुंचे, तो देखा कि चायपत्ती और ब्रेड दोनों खत्म। आपने फोन निकाला और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑर्डर प्लेस करके बाथरूम में नहाने चले गए।

आपके नहाकर निकलने से पहले ही दरवाजे पर दस्तक हो सकती है, सर... आपका ऑर्डर।

यह जादू है क्विक कॉमर्स का। इसमें आपकी जरूरत का सामान काफी कम समय में आपके पास पहुंच जाता है। अमूमन आधे घंटे से पहले। इस सर्विस ने शहरी डिजिटल उपभोक्ताओं के बीच अपनी गहरी पैठ बना ली है, उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। अब क्विक कॉमर्स कंपनियों की नजर छोटे शहरों औ कस्बों में रहने वाले उपभोक्ताओं पर है।

क्विक कॉमर्स की बड़ी कंपनियां?

फिलहाल क्विक कॉमर्स सेगमेंट में तीन बड़े खिलाड़ी हैं। जोमैटो का ब्लिंकइट, स्विगी का इंस्टामार्ट और जेप्टो। ये सभी एकदूसरे से आगे निकलने की होड़ में हैं, क्योंकि अभी इनके मार्केट शेयर में कोई बड़ा अंतर नहीं है।

समाचार एजेंसी आईएएनएस ने इंडस्ट्री एक्सपर्ट के हवाले से बताया कि क्विक ग्रॉसरी कॉमर्स के दुनिया के अन्य देशों में काफी कम सफल रहे, लेकिन भारत में वे कामयाबी की नई इबारत लिख रहे हैं।

हालांकि, पाकिस्तान में क्विक कॉमर्स कुछ हद तक सफल रहा। वहां किराने के सामान की इंस्टैंट डिलीवरी करने वाला एयरलिफ्ट एक्सप्रेस देश का पहला यूनिकॉर्न बनने की भी कगार था। लेकिन, वह भी जल्द ही बर्बाद हो गया।

भारत में क्यों सफल हुए क्विक कॉमर्स?

एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में जनसंख्या घनत्व काफी अधिक है। साथ ही, गली-गली में किराना स्टोरों की भी भरमार है। ऐसे में ब्लिंकइट और जेप्टो जैसी कंपनियों को काफी कम लागत में अपनी सेवाएं उपलब्ध कराने का मौका मिल जाता है।

युवा पीढ़ी (GenZ) हर रोज अपने जरूरत का सामान ऑनलाइन मंगा रही है। शुरुआत में ये प्लेटफॉर्म सिर्फ किराने का सामान डिलीवर करते थे। लेकिन, जल्द ही अपना दायरा सभी सेगमेंट तक फैला लिया। इसमें आटा-दाल से लेकर सब्जियां और साबुन-शैंपू के साथ शेविंग प्रोडक्ट्स तक शामिल हैं।

ग्राहक को क्विक कॉमर्स से सामान मंगाने में सहूलियत हो रही है। यहां कई बार मार्केट रेट से कम में चीजें मिल जाती हैं। आपको मार्केट भी जाना पड़ता। इससे आपका वक्त बचता है और आपको सामान भी अपने दरवाजे पर मिल जाता है।

क्विक कॉमर्स की बढ़ती वैल्यू

ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो ने इंस्टैंट ग्रोसरी डिलीवरी करने वाली ब्लिंकइट (Zomato-Blinkit Deal) को 2022 में

करीब साढ़े 4 हजार करोड़ रुपये में खरीद था, जो पहले ग्रोफर्स के नाम से जाना जाता था। प्रतिष्ठित ब्रोकरेज गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक, जोमैटो की कुल कमाई में उसके फूड डिलीवरी बिजनेस का कम, क्विक कॉमर्स की हिस्सेदारी अधिक है।

ब्लिंकइट के पास हाई SKU (स्टॉक कीपिंग यूनिट) की उपलब्धता है। उसका ऑर्डर फुलफिलमेंट रेट भी बेहतर है। उसके पास ग्राहकों का ज्यादा डेटा भी है। अपनी शानदार सर्विस की बदौलत उसका एवरेज ऑर्डर वैल्यू (AOV) इंडस्ट्री में सबसे अधिक है। इससे जोमैटो को अपना मुनाफा बढ़ाने में भी मदद मिली है।

डार्क स्टोर बढ़ा रहीं कंपनियां

क्विक कॉमर्स कंपनियां अपने डार्क स्टोर की संख्या लगातार बढ़ा रही हैं। डार्क स्टोर दरअसल कंपनियों के गोदाम की तरह होते हैं। यहां कंपनियां अपने प्रोडक्ट को स्टोर करती हैं, लेकिन आप यहां सीधे जाकर खरीदारी नहीं कर सकते। आपको ऑनलाइन ही ऑर्डर प्लेस करना होगा। फिर कंपनी उसकी डिलीवरी आपके बताए पते पर कर देगी।

कितना बड़ा है क्विक कॉमर्स मार्केट?

मार्केट इंटेलिजेंस फर्म रेडसीर की रिपोर्ट बताती है कि भारत का क्विक कॉमर्स मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। यह पिछले साल ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू (GMV) के मामले में सालाना आधार पर 77 फीसदी बढ़कर 2.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया है।

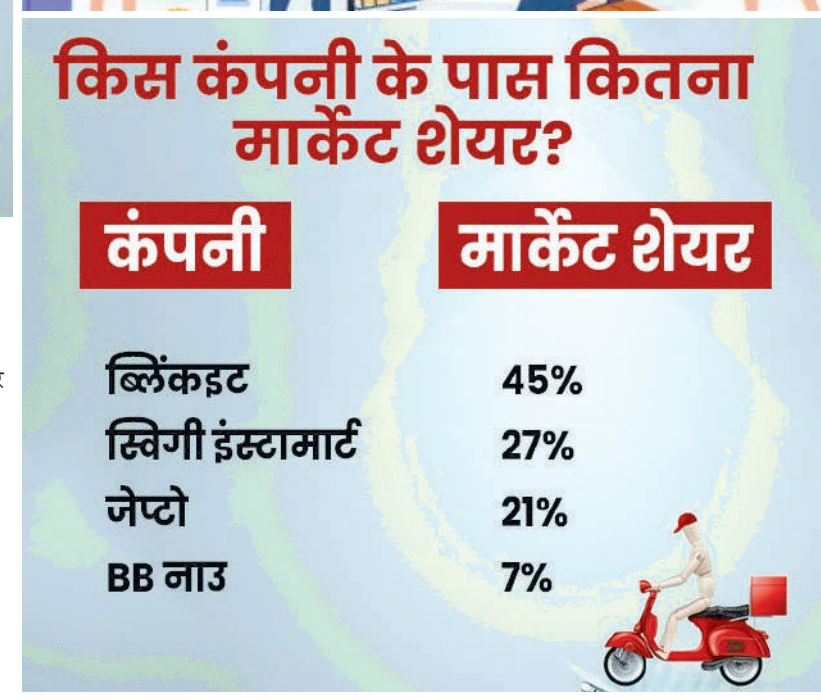

रिलायंस ने वायकॉम 18-स्टार इंडिया मर्जर के लिए CCI से मांगी मंजूरी, जानिए कैसा होगा ज्वाइंट वेंचर

परिवहन विशेष न्यूज

अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ने अपने वायकॉम18 और स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (SIPL) के मर्जर के लिए कंपीटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) से मंजूरी मांगी है। सीसीआई देश में फेयर ट्रेड रेगुलेटर है जो कारोबार जगत में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करता है। RIL ने अपनी नोटिस में यह भी कहा कि प्रस्तावित सौदे से भारत में प्रतिस्पर्धा पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा।

नई दिल्ली। अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ने अपने वायकॉम18 और स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (SIPL) के मर्जर के लिए कंपीटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) से मंजूरी मांगी है। इस मर्जर की वैल्यू 8.5 अरब डॉलर है। सीसीआई देश में फेयर ट्रेड रेगुलेटर है, जो कारोबार जगत में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करता है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने आवेदन में कहा है, 'इस प्रस्तावित सौदे का मकसद RIL के मालिकाना हक वाली वायकॉम18 के एंटरटेनमेंट बिजनेस और द वाल्ट डिज्नी कंपनी (TWDC) के पूर्ण स्वामित्व वाली स्टार इंडिया को मर्ज करना है। इस डील के बाद स्टार इंडिया का मालिकाना हक संयुक्त रूप से RIL के पास आ जाएगा।' RIL ने अपनी नोटिस में यह भी कहा कि प्रस्तावित सौदे से भारत में प्रतिस्पर्धा पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा।

क्या करते हैं Viacom18 और स्टार इंडिया

स्टार इंडिया फिलहाल टीवी प्रसारण, मोशन पिक्चर्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म समेत संचालन सहित कई मीडिया गतिविधियों में लगा हुआ है। यह अमेरिका की द वॉल्ट डिज्नी कंपनी (TWDC) की पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई है।

वहीं, Viacom18 भारत और दुनिया भर में टेलीविजन (टीवी) चैनलों के प्रसारण, ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म के संचालन का कारोबार करती है। यह मोशन पिक्चर्स के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का जिम्मा भी संभालता है।

कब हुई थी रिलायंस और डिज्नी की डील?

इस साल फरवरी में वैश्विक मीडिया दिग्गज वॉल्ट डिज्नी और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारत में अपने मीडिया ऑपरेशन को मर्ज करने का फैसला किया था। उन्होंने 70,000 करोड़ रुपये की बड़ी पूंजी बनाने के लिए बाध्यकारी समझौते पर साइन किया है।

इस डील के बाद बनने वाला ज्वाइंट वेंचर देश के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में सबसे बड़ी फर्म बन जाएगा। उसके पास कई भाषाओं में 100 से अधिक चैनल और दो प्रमुख ओटीटी प्लेटफॉर्म होंगे। उसकी पहुंच देशभर के करीब 75 करोड़ दर्शकों तक होगी।

कैसी होगी ज्वाइंट वेंचर की रूपरेखा?

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी ज्वाइंट वेंचर की चेयरपर्सन होंगी। वहीं, उदय शंकर वाइस-चेयरपर्सन होंगे। इस ज्वाइंट वेंचर में रिलायंस और उसके सहयोगियों की 63.16 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। वहीं, डिज्नी के पास बाकी 36.84 प्रतिशत हिस्सा रहेगा। रिलायंस ने ओटीटी कारोबार को बढ़ाने के लिए ज्वाइंट वेंचर में करीब 11,500 करोड़ रुपये का निवेश करने पर भी सहमति व्यक्त की है।

गर्मी के चलते लगातार बढ़ रही बिजली की मांग, 24 मई को नई रिकॉर्ड स्तर पर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड

परिवहन विशेष न्यूज

बिजली की अधिकतम मांग शुक्रवार को सीजन की नई ऊंचाई करीब 240 गीगावॉट पर पहुंच गई। बिजली की अधिकतम मांग या दिन में सबसे अधिक आपूर्ति शुक्रवार को 239.96 गीगावॉट दर्ज की गई जो इस साल गर्मी के मौसम में अब तक की सबसे अधिक है। गुरुवार को यह 236.59 गीगावॉट थी जबकि बुधवार को बिजली की अधिकतम मांग 235.06 गीगावॉट थी।

नई दिल्ली। देश के विभिन्न हिस्सों में बढ़ते पारे के कारण, एयर कंडीशनर और कूलर जैसे शीतलन उपकरणों के अत्यधिक उपयोग के कारण भारत की बिजली की मांग शुक्रवार को सीजन की नई ऊंचाई 239.96 गीगावॉट पर पहुंच गई।

बिजली मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, बिजली की अधिकतम मांग या दिन में सबसे अधिक आपूर्ति शुक्रवार को 239.96 गीगावॉट दर्ज की गई, जो इस साल गर्मी के मौसम में अब तक की सबसे अधिक है। बिजली मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, गुरुवार को यह 236.59 गीगावॉट थी, जबकि बुधवार को बिजली की अधिकतम मांग 235.06 गीगावॉट थी।

गर्मी के मौसम में टूटेंगे रिकॉर्ड

सितंबर 2023 में 243.27 गीगावॉट की सर्वकालिक उच्च शिखर बिजली मांग दर्ज की गई थी। इस गर्मी के मौसम में रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद है।

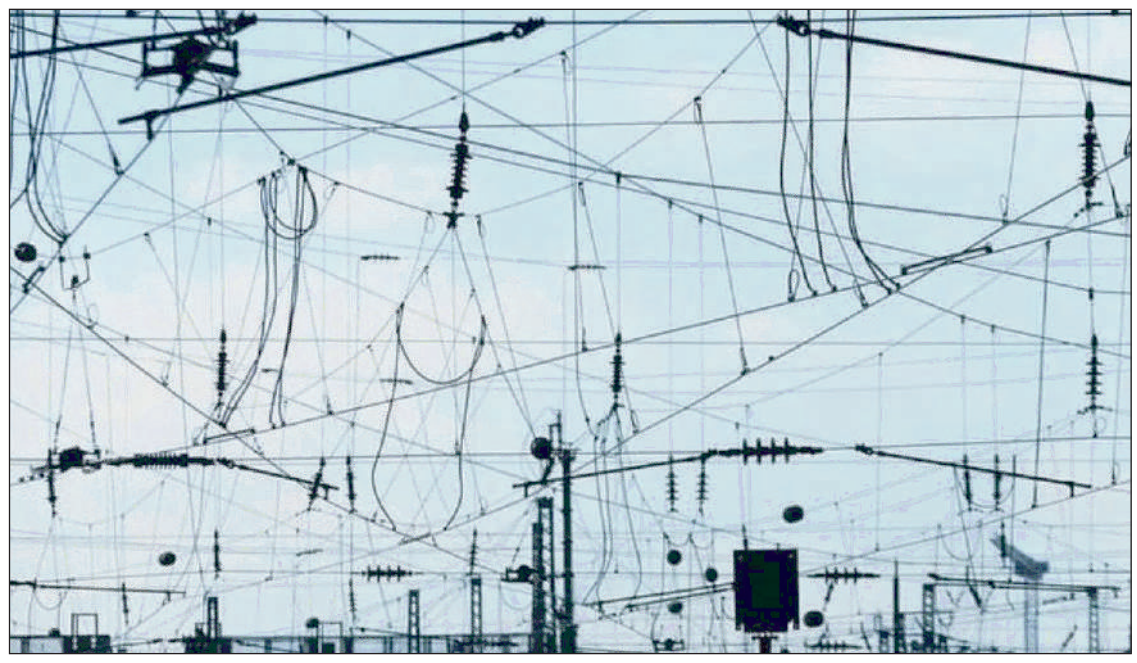

इस महीने की शुरुआत में, बिजली मंत्रालय ने मई के लिए दिन के समय 235 गीगावॉट और शाम के समय 225 गीगावॉट और जून 2024 के लिए दिन के दौरान 240 गीगावॉट और शाम के समय 235 गीगावॉट बिजली की अधिकतम मांग का अनुमान लगाया था।

उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि मई में बिजली की मांग पहले से ही 240 गीगावॉट के स्तर के आसपास है, जिसका अनुमान बिजली मंत्रालय ने जून महीने के लिए लगाया था। उन्होंने राय दी कि बिजली की मांग सितंबर 2023 में दर्ज किए गए 243.27 गीगावॉट के सर्वकालिक उच्च स्तर को पार करने के लिए और बढ़ सकती है।

इसके अलावा, बिजली मंत्रालय ने यह भी अनुमान लगाया है कि इस गर्मी के मौसम में बिजली की अधिकतम मांग 260 गीगावॉट तक पहुंच सकती है।

अप्रैल में बिजली की मांग 224.18 गीगावॉट

आंकड़ों से पता चलता है कि अप्रैल 2024 में अधिकतम बिजली की मांग 224.18 गीगावॉट थी, जब देश के विभिन्न हिस्सों में गर्मी के मौसम की शुरुआत देखी गई थी। मार्च में यह 221.82 गीगावॉट, फरवरी में 222.16 गीगावॉट और जनवरी में 223.51 गीगावॉट थी।

मई के दौरान, अधिकतम आपूर्ति 6 मई को 233 गीगावॉट और 21 मई को 233.80 गीगावॉट तक पहुंच गई। मई 2023 में यह 221.42 गीगावॉट दर्ज की गई थी।

पिछले सप्ताह, 18 मई को चरम बिजली आपूर्ति 229.57 गीगावॉट तक पहुंच गई, जबकि 15, 16 और 17 मई को यह लगभग 226 गीगावॉट थी। 4 मई को अधिकतम आपूर्ति 229.77 गीगावॉट और 20 मई को 228.71 गीगावॉट थी।

इस साल की शुरुआत में मार्च में, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अनुमान लगाया था कि भारत में इस साल अधिक गर्मी और अधिक लू वाले दिनों का अनुभव होने की संभावना है, अल नीनो की स्थिति कम से कम मई तक जारी रहने की भविष्यवाणी की गई है।

PFC, TVS मोटर्स और टाइटन के स्टॉक खरीदना चाहते हैं? जानिए क्या है टारगेट प्राइस और कहां रखें स्टॉप लॉस

परिवहन विशेष न्यूज

इस वक्त शेयर मार्केट में बुल रन चल रहा है। कई कंपनियों के शेयर निवेशकों को जमकर मुनाफा दे रहे हैं। लेकिन कुछ में गिरावट भी दिख रही है। ऐसे में कोई भी निवेश करने से पहले आपको सभी पहलुओं पर गौर कर लेना चाहिए। अगर आपके पहले से कोई शेयर हैं तो उसके बारे में भी जान लेना चाहिए कि उसमें मुनाफावसूली करके निकल जाना चाहिए या नहीं।

नई दिल्ली। इस वक्त शेयर मार्केट में बुल रन चल रहा है। कई कंपनियों के शेयर निवेशकों को जमकर मुनाफा दे रहे हैं। लेकिन, कुछ में गिरावट भी दिख रही है। ऐसे में कोई भी निवेश करने से पहले आपको सभी पहलुओं पर गौर कर लेना चाहिए। साथ ही, अगर आपके पहले से कोई शेयर हैं, तो उसके बारे में भी जान लेना चाहिए कि उसमें मुनाफावसूली करके निकल जाना सही रहेगा या स्टॉक अभी और बढ़ेगा।

हम आपकी आसानी के लिए तीन शेयरों- PFC, TVS मोटर्स और टाइटन के शेयरों के बारे में बता रहे हैं कि इनमें आपको क्या करना चाहिए। क्या इसमें खरीदारी सही रहेगी या फिर बेचकर निकल जाना चाहिए।

PFC में क्या जारी रहेगी चमक?

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (PFC) एक सरकारी कंपनी है, जो विद्युत क्षेत्र को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। इसके शेयरों ने पिछले एक साल में 260 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने में भी निवेशकों को कंपनी से करीब 54 फीसदी का मुनाफा हुआ है। PFC का शेयर शुक्रवार (24 मई) को 5.41 फीसदी उछलकर 492.55 रुपये पर बंद हुआ।

LKP सिक्योरिटीज में सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे (Rupak De) ने PFC को 493 रुपये पर खरीदने (Buy Rating) की सलाह दी है। उनका कहना है कि इस स्टॉक में तेजी का रुख दिख रहा है, क्योंकि यह क्रिटिकल मूविंग एवरेज से ऊपर बना हुआ है। साथ ही, मूल्य वृद्धि को वॉल्यूम में इजाफे का सपोर्ट मिला। यह नियर टर्म में 530 रुपये तक जा सकता है। वहीं, अगर स्टॉक नीचे आता है, तो आप 474 रुपये का स्टॉप लॉस रख सकते हैं।

टाटा ग्रुप की टाइटन ने पिछले दिनों तिमाही नतीजे जारी किए थे, जो बाजार की उम्मीद के हिसाब नहीं थे। लिहाजा, इसमें भारी बिकवाली भी हुई थी। पिछले एक महीने की बात करें, तो टाइटन के शेयर से निवेशकों को करीब साढ़े चार फीसदी का नेगेटिव रिटर्न मिला है। वहीं, इस साल यानी 2024 में अब तक टाइटन ने 7 फीसदी से अधिक का नेगेटिव रिटर्न दिया है।

TVS मोटर्स की कितनी तेज रहेगी रफ्तार?

इस साल अच्छे मानसून की संभावना के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। इसका फायदा FMCG और ऑटोमोबाइल सेक्टर को मिलने की उम्मीद है। खासकर, दोपहिया गाड़ियों की बिक्री में तेजी आ सकती है। इसका फायदा TVS मोटर्स को भी मिलने की उम्मीद है। LPK सिक्योरिटीज का कहना है कि टीवीएस मोटर्स ने डेली चार्ट में कंसालिडेशन ब्रेकआउट दिया है और अपने 24 दिन एक्सपोर्टेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) के ऊपर कारोबार कर है। इससे संकेत शॉर्ट टर्म में स्ट्रांग मोमेंटम का संकेत मिलता है।

LPK सिक्योरिटीज ने टीवीएस मोटर्स को 2246 रुपये पर खरीदने की सलाह दी है। उसका कहना है कि 2230 से 2250 रुपये के बीच खरीदकारी करके टीवीएस मोटर्स में लॉन्ग पोजिशन बनाई जा सकती है। इसकी टारगेट प्राइस 2370 रुपये है। LPK सिक्योरिटीज ने टीवीएस मोटर्स में स्टॉप लॉस 2160 रुपये रखने की सलाह दी है।

टाटा ग्रुप के टाइटन में क्या करें?

टाटा ग्रुप की टाइटन ने पिछले दिनों तिमाही नतीजे जारी किए थे, जो बाजार की उम्मीद के हिसाब नहीं थे। लिहाजा, इसमें भारी बिकवाली भी हुई थी। पिछले एक महीने की बात करें, तो टाइटन के शेयर से निवेशकों को करीब साढ़े चार फीसदी का नेगेटिव रिटर्न मिला है। वहीं, इस साल यानी 2024 में अब तक टाइटन ने 7 फीसदी से अधिक का नेगेटिव रिटर्न दिया है। शुक्रवार को इसके शेयर 1.19 फीसदी की गिरावट के साथ 3,411.00 रुपये पर बंद हुआ।

LPK सिक्योरिटीज का मानना है कि टाइटन में फिलहाल तेजी की गुंजाइश नजर नहीं आती। उसने इस स्टॉक को बेचने की सलाह दी है। LPK सिक्योरिटीज का कहना है कि डेली चार्ट में कमजोर दिख रहा है, जो अल्पावधि में संभावित मंदी का संकेत दे रहा है। हाई लेवल पर यह 3460 के स्तर पर शॉर्ट टर्म रेजिटेंस के रूप में काम कर सकता है। निचले स्तर पर यह 3300 की ओर बढ़ सकता है।

इस वजह से जल्द बंद होने जा रहा है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन? यहां शिफ्ट होंगी सभी ट्रेनें, देखें लिस्ट

स्टेशन पुनर्विकास योजना के तहत नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को इस साल के अंत तक बंद करने पर विचार किया जा रहा है। स्टेशन के बंद होने के बाद तेजी से इसके पुनर्विकास का काम शुरू हो सकेगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रोजाना लगभग 300 ट्रेनें चलती हैं। करीब 6 लाख से ज्यादा यात्री नई दिल्ली स्टेशन से आवागमन करते है।

नई दिल्ली। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए ये जरूरी खबर है। कुछ समय के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को बंद किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक, स्टेशन हमेशा के लिए बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि यह कुछ समय के लिए इसे बंद करने की तैयारी की जा रही है। भारतीय रेलवे स्टेशन की पुनर्विकास यानी रीडेवलपमेंट योजना के तहत इसे कुछ समय के लिए बंद करेगा। ताकि स्टेशन का काम तेजी से किए जा सके।

दरअसल, भारतीय रेलवे ने देश के करीब 1300 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास प्लान बनाया है। इसी प्लान के तहत नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का भी पुनर्विकास और कायाकल्प होना है। पहले स्टेशन के रीडेवलपमेंट का काम एक साथ करने की योजना थी, लेकिन ताजा जानकारी के अनुसार अब इसे अलग-अलग चरणों में किए जाने पर विचार चल रहा है। केंद्र सरकार के साल 2023 के रेल मंत्रालय बजट में भी इसे लेकर जानकारी दी गई थी।

जानकारी के अनुसार, लोकसभा चुनाव के बाद ही टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद स्टेशन के आने वाले छह से सात माह के भीतर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के काम को पूरे होने में करीब चार से पांच साल तक का समय लग सकता है। 2028 के अंत तक या 2029 तक बनकर पूरा तैयार हो जाएगा।

इन स्टेशनों से शुरू होगी ट्रेन

स्टेशन निर्माण कार्य के चलते करीब चार से पांच साल तक ट्रेनों के स्टेशन बदले जाएंगे। इससे यात्रियों को भी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। पुनर्विकास योजना के तहत नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को इस साल के अंत तक बंद करने पर विचार किया जा रहा है। स्टेशन के बंद होने के बाद तेजी से इसके पुनर्विकास का काम शुरू हो सकेगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रोजाना लगभग 300 ट्रेनें चलती हैं। करीब 6 लाख से ज्यादा यात्री नई दिल्ली स्टेशन से आवागमन करते हैं।

जानकारी के मुताबिक, नई दिल्ली स्टेशन के रीडेवलपमेंट के चलते ट्रेनों को आसपास के स्टेशनों पर शिफ्ट किया जाएगा। उत्तर और पूर्व की ओर जाने वाले ट्रेन आनंद विहार रेलवे स्टेशन से चलाई जाएगी। जबकि पंजाब, हरियाणा जाने वालीं ट्रेनें सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन शिफ्ट की जा सकती हैं। इसी तरह राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात समेत दक्षिण भारत की राज्यों के लिए जाने वाली ट्रेनों को दिल्ली कैंट और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर शिफ्ट किया जा सकता है। इसके अलावा बची हुई ट्रेनों को गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के अलावा दिल्ली के अन्य स्टेशनों पर भी शिफ्ट किया जा सकता है।

30 सेकंड में फैली आग, लपटों के बीच कोहराम; प्रत्यक्षदर्शियों ने बताई भयावह पल की दास्तान

शनिवार का दिन गुजरात के लिए काला दिन साबित हुआ। राजकोट के गेम जोन में भीषण आग लग गई, जिसमें 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 10 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। पीएम मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने इस दुखद घटना पर शोक प्रकट किया है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि वो पल बहुत ही डरावना था। चारों तरफ आग ही आग फैली थी और लोगों की चीख पुकार सुनाई दे रही थी। आगे देखिए अग्निकांड की तस्वीरें

गुजरात के राजकोट में शनिवार शाम पांच बजे भीड़भाड़ भरे गेम जोन में भीषण आग लग गई। हादसे में 10 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है।

30 सेकंड के अंदर पूरे गेम जोन में फैली आग

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि गेम जोन में कई जगह मरम्मत और रेनोवेशन का काम चल रहा था। बड़ी संख्या में प्लाई के टुकड़े और लकड़ियां फैली हुई थीं। आग लगते ही ये भी उसकी चपेट में आ गए और 30 सेकंड के अंदर आग पूरे गेम जोन में फैल गई।

करीब तीन घंटे बाद आग पर पाया काबू

आग से पूरा गेम जोन जलकर राख हो गया है। आग पर करीब तीन घंटे में काबू पाया जा सका। अधिकारियों का कहना है कि मृतकों के शव बुरी तरह से झुलस गए हैं।

शवों की पहचान के लिए होगा डीएनए टेस्ट

बताया गया है कि बुरी तरह से झुलसने के कारण कई शवों की अभी शिनाख्त नहीं हो सकी है। पहचान के लिए डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

क्या औद्योगिक एवं तकनीकी जासूसी है चीन की कामयाबी का राज

अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इन दिनों एक खबर प्रमुखता बनाए हुए है। जिसका सार यह है कि अमरीका, ऑस्ट्रेलिया समेत पश्चिम के देशों की इन दिनों एक नई चुनौती सामने आने के बाद नींद उड़ी हुई है। यह चुनौती पैदा हुई है चीन द्वारा कथित तौर पर की जा रही नए तरीके...

अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इन दिनों एक खबर प्रमुखता बनाए हुए है। जिसका सार यह है कि अमरीका, ऑस्ट्रेलिया समेत पश्चिम के देशों की इन दिनों एक नई चुनौती सामने आने के बाद नींद उड़ी हुई है। यह चुनौती पैदा हुई है चीन द्वारा कथित तौर पर की जा रही नए तरीके की जासूसी से। विश्व में बड़े प्लेयर की भूमिका निभाने वाले इन देशों की खुफिया एजेंसियां आरोप लगा रही हैं कि चीन तकनीक और औद्योगिक जासूसी के काम में बरसों से लिप्त है लेकिन इस तरफ किसी का सहजता से ध्यान नहीं गया। यह मामला खुफिया एजेंसियों द्वारा जिस तरह के मामलों की जासूसी की जाती है उससे बिल्कुल ही अलग है।

बी.बी.सी. को दिए इंटरव्यू में ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा और खुफिया संगठन (ASIO) माईक ब्रगेस का कथन प्रकाशित हुआ है जिसमें कहा गया है कि उनकी एजेंसी बीते 74 सालों में इतनी व्यस्त कभी नहीं रही जितनी अब व्यस्त है। पश्चिमी देशों ने इस खतरे को समझने में देरी की है। दरअसल हम सामूहिक तौर पर चूक गए हैं। कमर्शियल जासूसी बिल्कुल अलग मामला है। ऐसे मामलों पर अब ब्रिटेन की एम 16 विदेशी खुफिया एजेंसी प्रमुख का भी बयान इंटरनैशनल मीडिया में सामने आया है जिसमें कहा गया है कि चीन ये लंबे समय से करता आ रहा है। तो क्या चीन की उत्पादन और निर्माण में दुनिया भर में बादशाहत या कहें राज करने की स्थिति तक पहुंचने में इस कमर्शियल जासूसी का ही बड़ा योगदान है? इसका जवाब हां में निकल कर आ रहा है क्योंकि पश्चिम ने जो आरोप लगाया है उसमें कहा गया है कि चीन का कमर्शियल जासूसी नैटवर्क एकत्रित की गई सूचनाओं को चीन की कंपनियों से सांझा करता है। जाहिर-सी बात है इन सूचनाओं का उपयोग चीनी कंपनियां अपने प्रोडक्ट के निर्माण और गुणवत्ता और नए आविष्कारों के लिए करती हैं। इसे समझने के लिए हमें 80 के दशक में जाना होगा।

वर्ष 1980 में चीन ने पहली बार 4 स्पैशल इकोनॉमिक जोन बनाए थे। जिन्हें एस.ई.जैड. कहा जाता है। यानी आज से तकरीबन 43 वर्ष पहले चीन ने बड़े औद्योगिक स्तर पर वस्तुओं के निर्माण की दिशा में बड़ा और ठोस कदम बढ़ा लिया था। इससे पहले आयरलैंड में 1950 में एस.ई.जैड. स्थापित किया गया था। उसके बाद कुछ अन्य देशों में भी ऐसे प्रयास हुए लेकिन वहां वो सफलता शायद नहीं मिल पाई जो चीन ने हासिल कर ली। चीन एस.ई.जैड. के माध्यम से न केवल विश्व में बड़ा निर्माता बन कर उभरा है, बल्कि विश्व की कई बड़ी कंपनियों को अपने उद्योग चीन में स्थापित करने के लिए प्रेरित करने में कामयाब रहा। सस्ती लागत और सस्ते कामगार इसका कारण शायद रहे होंगे।

आज दुनिया भर के देशों में अनेकों वस्तुओं के निर्माण में काम आने वाले कच्चे माल (रॉ मैटीरियल) का जहां मुख्य आपूर्तिकत्र्ता है वहीं विश्व के अधिकांश देशों के बाजार चीन के तैयार माल से पटे पड़े हैं। जहां चीन का तैयार माल खूब बिक रहा है उन देशों की सूची में जहां अफ्रीका के गरीबी से जूझ रहे देश शामिल हैं वहीं चीन की मार्कीट में शुमार देशों में अमरीका जैसे विकसित और भारत जैसे विकासशील देश भी शामिल हैं। चीन ने न केवल अपने यहां बड़े और विशाल एस.ई.जैड. विकसित किए बल्कि अफ्रीकी देशों की भी एस.ई.जैड. शुरू करने में न केवल मदद की बल्कि उन्हें वित्तीय मदद भी की।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार चीन ने नाइजीरिया, डिजीबूटी, केन्या, जांबिया, मॉरीशस, मॉरिटानिया, अल्जीरिया और इजिप्ट जैसे देशों की एस.ई.जैड. स्थापित करने में मदद की और उन्हें चाइना अफ्रीका डिवैल्पमैंट फंड तथा फोरम ऑन चाईना अफ्रीका कोऑपरेशन के माध्यम से लंबी अवधि के लिए कर्ज भी दिया बदले में चीन ने अपने हितों को प्राथमिकता दी, वहां के बाजार इसका प्रमाण हैं। चीन आज दुनिया में छोटी छोटी वस्तुओं से लेकर बड़ी मशीनरी, कैमिकल्स सहित अनेक क्षेत्रों के लिए मुख्य आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। भारत में भी एस.ई.जैड. की स्थापना का कार्य वर्ष 2005 के बाद विदेश निवेश कानून बनने के बाद चर्चा में आया था। आज देश में 359 एस.ई.जैड. पर कार्य चल रहा है और 425 को मंजूरी दी जा चुकी है। इसमें आधे से ज्यादा को मंजूरी 2005 के बाद प्राप्त हुई है।

आज जब पश्चिम के देश चीन द्वारा कथित तौर पर की जा रही कमर्शियल एवं औद्योगिक जासूसी को लेकर चिंतित हैं और इस पर न केवल अब खुल कर बोल रहे हैं बल्कि चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में भारत को निर्माण और निवेश के विषय को और ज्यादा गंभीरता से लेते हुए अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने पर जोर देना होगा। चीन का आबादी में मुकाबला भारत के साथ है लेकिन इससे बड़ा और असली मुकाबला उत्पादन और खपत के बाजार में दुनिया के लिए महत्वपूर्ण देश कौन होगा, इसको लेकर भी है। भारत के लिए यह अवसर ऐसा अवसर है जिसे गंवाने का जोखिम नहीं लिया जा सकता।

-राजेंद्र कुमार राज

महेश आरोग्य किट जीवन रक्षक के लिए कारगर -महंत लक्ष्मण दास त्यागी

दक्षिण राजस्थान प्रादेशिक माहेश्वरी सभा का सातवां शिविर आयोजित

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

भीलवाड़ा। दक्षिण राजस्थान प्रादेशिक माहेश्वरी सभा द्वारा हृदय घात से बचाव के लिए महेश आरोग्य किट का निशुल्क वितरण के अवसर पर पंचमुखी दरबार के महंत लक्ष्मण दास त्यागी ने कहा कि महेश आरोग्य किट जीवन रक्षक के लिए कारगर साबित होगा, इससे पूर्व प्रादेशिक सभा के सातवें शिविर का शुभारंभ।

महंत लक्ष्मण दास त्यागी पंचमुखी दरबार , प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम चेचानी नगर परिषद सभापति राकेश पाठक, सत्यनारायण डाड ,उदयलाल समदानी, मधु जाजू ,सीमा कोगटा ने भगवान महेश के द्वीप प्रज्वलन कर विधिवत शुभारंभ किया गया महेश आरोग्य किट वितरण स्व रामगोपाल बाहेती की स्मृति में एवं छीतरमल, सत्यनारायण रमेश बाहेती के सहयोग से आयोजित किया गया।

इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम चेचाणी ने कहा कि महा अभियान के तहत प्रदेश के नौ जिलों में हृदय घात बचाव के महेश आरोग्य किट वितरित किए जाएंगे इसमें शाहपुरा, निंम्बाहेड़ा ,उदयपुर एवं राजसमंद में आगामी दिनों किट वितरण के कार्यक्रम होंगे प्रदेश कार्यालय मंत्री देवेंद्र सोमानी ने किट में रखी गई तीन तरह की गोलियों के बारे में जानकारी देते हुए इसे किस तरह से लेना है सभी उपस्थित गणमान्य को विस्तृत बताया गया,

किट वितरण कार्यक्रम प्रभारी महावीर समदानी ने जानकारी देते हुए बताया गए कि युवा, महिलाएं, बुजुर्ग लोगों ने बड़े उत्साह से महेश आरोग्य किट निशुल्क प्राप्त किये इस अवसर पर प्रहलाद राय लड्ढा, कृष्ण गोपाल जागेटिया ,बालू लाल समदानी, अशोक बाहेती पुराना शहर ,कैलाश बाहेती, सत्यनारायण तोतला, एडवोकेटअशोक काबरा, रामकिशन सोनी, रामगोपाल राठी ,प्रहलाद अजमेरा, हरीश पोरवाल, भारती बाहेती ,रीना डाड, अर्चित मुन्दडा, श्यामलाल डाड ,महेंद्र काकानी ,राजेश तोषनीवाल, विकास समदानी, सुरेश जाजू, सत्यनारायण सोमानी, ओमप्रकाश बिरला मान्डल, राजेंद्र कचोलिया ,दिलीप तोषनीवाल, मोनू तोषनीवाल,राधेश्याम सोमानी मरुधरा,कैलाश ईनाणी, मधुबाला महाजन, ओम गन्दोडिया ,दिनेश पटवारी, एडवोकेट गोपाल अजमेरा, रमेश बाहेती आजाद चौक उपस्थित थे।

नहीं खुल सका स्क्रैप सेंटर, सड़कों पर दौड़ रहे 20 साल से पुराने 70 हजार वाहन

परिवहन विशेष न्यूज

बरेली। नई वाहन स्क्रैप नीति लागू हुए दो वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन जिले में अब तक स्क्रैप सेंटर नहीं खुल सका है। एक स्क्रैप सेंटर बहेड़ी में खोलने के लिए निजी फर्म ने आवेदन किया था। स्थानीय स्तर पर प्रक्रिया पूरी करने के बाद अधिकारियों ने स्वीकृति के लिए फाइल परिवहन मुख्यालय भेजी है, लेकिन अब तक इसे मंजूरी नहीं मिल सकी। स्थिति ये है कि जिले में 70 हजार से ज्यादा ऐसे वाहन हैं जो 20 वर्ष पूरे कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी सड़कों पर दौड़ रहे हैं।

जिले में कुल 9,03,814 वाहन हैं। इनमें 3,79,690 ऐसे वाहन हैं जिनका पंजीकरण 2019 से पहले हुआ था। इन वाहनों में 70,457 ऐसे वाहन हैं जो 15 और 20 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं और स्क्रैप की श्रेणी में आ गए हैं। इसके अलावा 15 वर्ष पूरे कर चुके तीन हजार से ज्यादा वाहनों का हाल के महीनों में अगले पांच साल के लिए री-रजिस्ट्रेशन कराया गया है।

नई स्क्रैप नीति के तहत अगर कोई वाहन स्वामी वाहन के 15 या 20 साल पूरे होने पर उसे स्क्रैप कराता है तो उसे वाहन के पंजीकरण और वन टाइम टैक्स पर 15 प्रतिशत तक की छूट दी जाती है। इसके लिए वाहन स्वामी को वाहन स्क्रैप कराने के बाद स्क्रैप सेंटर से मिलने वाले प्रमाण पत्र को नए वाहन के रजिस्ट्रेशन के साथ देना होता है। जिले में कोई स्क्रैप सेंटर न होने के कारण अब तक एक भी वाहन स्वामी को पंजीकरण और वन टाइम टैक्स में छूट नहीं मिली है। 260 से ज्यादा सरकारी वाहन भी कार्यालयों में खड़े स्क्रैप के इंतजार में कबाड़ में तब्दील हो रहे हैं।

एक जून से बदलेगा नियम, 20 साल से अधिक पुराने वाहनों पर जुर्माना

एक तरफ तो अभी स्क्रैप सेंटर नहीं खुला और दूसरी ओर एक जून से पुराने वाहनों के संचालन को लेकर नियम बदलने जा रहा है। नए नियम में अगर कोई वाहन 20 साल से ज्यादा पुराना सड़क पर चलता हुआ पाया जाएगा तो उसे पकड़कर सीधे स्क्रैप सेंटर भेजने के साथ ही वाहन स्वामी पर जुर्माना भी लगाने का प्रावधान है। इसके अलावा नए वाहन के पंजीकरण में उसे कोई छूट भी नहीं देने की बात कही गई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि बिना स्क्रैप सेंटर खोले पुराने वाहनों पर सख्ती क्यों की जाएगी?

15 साल पुराने वाहनों के री-रजिस्ट्रेशन को फिटनेस जरूरी

15 साल पुराने हो चुके निजी वाहनों को अगले पांच साल तक री-रजिस्ट्रेशन कर चलाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए वाहन की फिटनेस जरूरी होती है। ऐसे में वाहन को अगर फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं मिलता तो री-रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो सकता। यानी ऐसे पुराने वाहनों को स्क्रैप सेंटर भेजने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं होता। चूंकि यहां स्क्रैप सेंटर नहीं है, ऐसे में मजबूरन वाहन स्वामी को परेशान होना पड़ता है।

स्क्रैप नीति को लेकर एक जून से नियमों में बदलाव हो जाएगा। स्क्रैप सेंटर खोलने के लिए बहेड़ी की निजी फर्म ने आवेदन किया था। स्थानीय स्तर पर प्रक्रिया पूरी कर इसे स्वीकृति के लिए मुख्यालय भेज दिया गया है। 15 या 20 साल पुराने वाहन को स्क्रैप कराने पर वाहन स्वामी को नए वाहन के रजिस्ट्रेशन में 15 फीसदी तक छूट का प्रावधान भी है। अब तक जिले में किसी ने इस छूट का लाभ नहीं लिया है।

-मनोज कुमार, एआरटीओ प्रशासन/नोडल अधिकारी

बापूनगर में दांतो के अस्पताल का शुभारंभ

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

भीलवाड़ा। वैसे तो भीलवाड़ा शहर में हर बीमारी के इलाज के लिए अनेकों अस्पताल हैं। इसी क्रम में अब बापूनगर में भी दांतो के अस्पताल का आज तड़के भव्य शुभारंभ किया गया। दन्त शल्य विशेषज्ञ और कॉस्मेटोलॉजीस्ट डॉक्टर पल्लवी जौशी ने बताया कि ₹अनघ₹ नाम से खुले अस्पताल का उनके पिता श्याम लाल जौशी एवं माता पवन जौशी ने फीता काट ठाकुरजी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर दांतो के अस्पताल का भव्य शुभारंभ किया।

शहर के बापूनगर स्थित गौतम धाम के पास कांता विला में खुले दांतो के इस अस्पताल में परामर्श समय प्रातः 10 बजे से शांय 8 बजे के दौरान एक्स रे द्वारा दाँतो की जाँच, दाँतो की सफाई, दाँत की नसों का इलाज, खराब दांत निकालना, बत्तीसी व नये फिक्स दाँत लगाना, दांतों में मसाला भरना, टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा करना, हड्डी में स्क्रू डालना व दांत लगाना जैसे कार्यो के साथ ही चमड़ी और बालों का लेजर तकनीक से इलाज, लेजर द्वारा शरीर के अनचाहे बाल हटाना, लेजर द्वारा टैटू, तिल, मस्सों व बर्थ

चिन्ह हटाना, त्वचा के दाग धब्बे, धूप से कालापन, मुँहासे के दाग का इलाज, झाइयों व झुर्रियों का इलाज, बालों का पतलापन, झड़ना व गंजेपन का इलाज किया जाएगा।

डॉक्टर पल्लवी जौशी ने बताया कि अस्पताल के शुभारंभ के अवसर पर रोगियों को विशेष लाभ दिया जाएगा। जिसमें पहले 100 रोगियों के लिए 1 जून तक 15 प्रतिशत की छूट रहेगी।

इस अवसर पर नमिता चौहान, रोहित व्यास, अभिषेक शर्मा, शुभम त्रिपाठी, शब्बीर मोहम्मद सहित कई गणमान्य मौजूद रहे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023